REPORT OF THE COMMITTEE ON PETITIONS

SHRI RAM NIWAS MlRDHA (Rajasthan): Sir, I be to present the -Sixty-sixth Report of the Committee ,on Petitions *on* the petition signed by Dr. R. C. Tyagi regarding the working conditions etc, of the scientists in the Solid State Physics Laboratory under the Defence Research and Development Organisation.

REPORT OF THE COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

SHRI SHRIKANT VERMA (Madhya Pradesh): Sir, I beg to lay on the Table a copy (in English and Hindi) of the Seventh Report of the Committee on Public Udertakings on Action Taken by Government On the recommendations contained in the Forty-fourth Report of the Committee on Public Undertakings (Sixth Lok Sabha) o$_n$ Tea Trading Corporation of India Ltd.—General Functioning and Internal Sales (Ministry of Commerce, Department of Commerce).

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Problem of growing unemployment in the country

श्री शिव चन्द्र झा (बिहार) : इसी कालिंग अटेंशन पर मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है । आप विषय देखिये कालिंग अटेंशन का । अनइंप्लायमेंट पर जो रिटन जवाब आता है और जिस रूप में यहां नाम रखे गये हैं उनसे ऐसा मालूम होता है कि एक प्लान्ड रूप में यह सब किया गया है और एक कायदे से नाम जोड़ कर दिये गये हैं और ऐसा मालूम होता है कि प्रशराइज करके ऐसा कराया गया है । हम सब इसमें इंटरेस्टेड हैं इसलिये मैं चाहता हूं कि आखिर इसके लिए कोई स्टैंडर्ड बनाया जाये ।

श्री उपसभापति : जिन माननीय सदस्यों ने कालिंग अटेंशन दिया है उनके नाम इसमें दिये गये हैं । आपके विचार दूसरे हो सकते हैं, लेकिन चेयरमेन साहब ने जो उचित समझा है, किया हैं ।

श्री शिव चन्द्र झा : मैं आप दोनों को ही कहूंगा ।

श्री उपसभापति : ठीक है, लेकिन उनका विचार ऐसा नहीं है ।

PROF. SOURENDRA BHATTA-CHARJEE (West Bengal): I have a submission to make. Th$_e$ Calling Attention deals with a very important issue and I would request you to devote enough time to this issue hi order to do justice and to allow us to express our genuine conce$_{rn}$ for thi$_s$ very serious problem, particularly for the younger generation.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: There is enough time.

SHRI KALP NATH RAI (Uttar Pradesh): Sir, I call the attention of the Minister of Planning and Labour to the problem of growing unemployment in the country and action taken oy Government in this regard.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR (SHRIMATI RAM DULARI SINHA): Sir, Government are aware of the seriousness of the unemployment problem prevailing in the country. Keeping in view the unemployment situation prevailing in the country. Government decided that a progressive reduction of unemployment should be one of the principal objectives of th$_e$ Sixth Five Year Plan. The Sixth Five Year Plan ha$_s$ since been finalised and it indicates in detail the policies and measures envisaged by Government to tackle unemployment. Some of the major programmes with significant employment potential are:—

[Shrimati Ram Dulari Sinha]

(i) Generation of increasing employment opportunities in agriculture and allied sectors through massive irrigation programmes (with a high component of minor irrigation), improved availability of agricultural inputs especially fo$_r$ small farmers etc.

(ii) Extension of the Integrated Rural Development Programme to all the blocks in the country. This has already been done. About 1.5 crore families would be benefited during 1980—35 by this programme and brought above the poverty-line.

(iii) Operation Flood II Dairy Development Project is expected to benefit about 80 lakh basically milk producing families during the Sixth Plan period. Other dairy development schemes would also benefit about 50 lakh additional families.

(iv) The National Rural Employment Programme (NREP) would cover all the blocks in the country and provide wage employment, particularly during the slack agricultural season. About 30 t$_0$ 40 crores man-days of employment pe$_r$ year would be generated by the Programme.

(v) Th$_e$ Plan allocations for small scale, Khadi & Village Industries, sectors whichl provide the largest number of jobs in the rural areas nexf; to agriculture, have been increased. Programmes of assistance for the development of Khadi & Village and Small industries including handlooms, handicrafts, sericulture, etc. are expected to benefit an additional 90 lakh persons during the Plan period.

(Mi) Various components of the Minimum Needs Programme are likely to generate considerable employment in construction, industries and the expansion of the infrastructure and social services brought about by the programme would also generate Substantial indirect em-ploj ment.

(vii) The TRYSEM would train-2 lakh rural youth every yea$_r$ equipping them for self-employment and these persons would be assisted in setting up their own ventures. The Special Employment Schemes being implemented by several State Governments would be further strengthened and extended.

(viii) Works for environmental sanitation, slum improvement, tree plantation, construction of houses for the economically handicapped, etc. would help to increase the incomes of the unemployed urban-poor.

(ix) An important feature of the Plan is the decentralised strategy for manpower planning and employment generation proposed to be adopted. Th$_e$ District Manpower Planning & Employment Generation Councils proposed to be set up,, would draw up strategies and plans for employment generation in the districts.

(x) A new deal for the self-employed i$_s$ another important feature of the Sixth Plan. The Plan proposed a package of policy measures, consisting of guidance, credit facilities, training, marketing and other measures for promoting self-employment of individuals and groups of individuals.

2. The implementation of the programmes included in the Sixth Five-Year Plan is expected to increase employment in the entire economy from 15.1 crore standard person-years at th$_e$ beginning of the Sixth Plan period to 18.'5 crore standard person-years at the end of the Plan period. Though the increase in amployment in standard person-years is about 3.4 crores, the actual number of beneficiaries is expected to be much more since not every member of the labour force mav be a full-time worker during the-entire year.

श्री कल्पनाथ राय : आदरणीय उप-सभापति महोदय, मैं सर्वप्रथम प्लानिंग मिनिस्टर और सरकार को यह बधाई देना

चाहता हूं कि उन्होंने छठी पंचवर्षीय योजना का मसविदा सब से कम समय में देश के सामने प्रस्तुत किया है और उसके माध्यम से बेकारी की समस्या को हल करने की दिशा में ठोस एवं सही कदम उठाए हैं। लेकिन बेकारी की समस्या इसी समय, और वह भी पढ़े लिखे बेकारों की संख्या ऐसे बढ़ रही है कि एक बहुत ही भयानक स्थिति पैदा हो रही है।

उपसभापति महोदय, मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि पढ़े लिखें, बेकार लोगों और गैर-पढ़े लिखे बेकारों के सम्बन्ध में आजादी के बाद किस हिसाब से बढ़ोत्तरी हो रही है। इस सम्बन्ध में मुझे चार पांच सवाल सरकार से पूछने हैं। पहला यह है कि क्या सरकार बतायेगी कि इस समय देश में पढ़े लिखे कितने बेकार हैं? इस समय बिना पढ़े लिखे लोग कितने बेकार हैं? दोनों की संख्या मैं सरकार से जानना चाहूंगा। क्या सरकार यह बतायेगी कि देश की मैनपावर का इस्तेमाल करने के लिये वह कैसी योजना बना रही है? छठी पंचवर्षीय योजना में कितने बेकारों को काम मिलेगा? क्या सरकार यह बतायेगी कि बढ़ती हुई पापुलेशन को मद्देनजर रखते हुए छठी पंचवर्षीय योजना के बाद इस देश में कितने बेकारों के बढ़ जाने की संभावना है? क्या सरकार जॉब ओरिएन्टेड पढ़े लिखों को प्राथमिकता देगी? आज विश्वविद्यालय और डिग्री कालेजों की संख्या बढ़ती जा रही है। एम० ए०, बी० एज० पास लड़के आज किसी काम के लिये सिद्ध नहीं हो रहे हैं। क्या सरकार भी ऐसा करेगी जैसा कि रूस में या समाजवादी मुल्क में होता है कि जब ओरिएन्टेड एजुकेशन यानी हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट पास होने के बाद किसी लड़के का क्या टेस्ट है उसके अनुकूल उनको पालिटेकनिक की शिक्षा दी जाती है और शिक्षा प्राप्त होने के बाद ऐसे लोगों को रोजगार के अवसर सुलभ किये जाते हैं। क्या सरकार यह बतायेगी कि जो नेशनाइज्ड बैंक्स हैं उनकी पूंजी का कितना प्रतिशत इस मुल्क की बेकारी की समस्या को हल करने के लिये खर्च किया जा रहा है? क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी जैसा कि बिहार सरकार ने अपनी कबिनेट में प्रस्ताव पास किया है कि हम कुछ प्रखंडों में या देश के कुछ हिस्सों में जो पढ़े लिख बेकार हैं उनको एलाउंस देंगे और जब उनको काम मिल जाएगा तो एलाउंस बन्द कर दिया जायेगा तो क्या यह सरकार इस पर भी गौर कर रही है? सोशल सेक्योरिटी सिस्टम जैसा कि कई मुल्कों में है, हमारे बिहार में भी है तो क्या यह सरकार इस तरह की स्कीमें पूरे राष्ट्रीय पैमाने पर लागू करने का विचार कर रही है कि हम अगर बेकारों को काम नहीं दे पायेंगे तो एलाउंस देंगे? सब से बड़ी बात यह है कि हमारे मुल्क में मैनपावर है जब कि विदेशी मुल्कों में मनी पावर है या डालर पावर है। हमारे पास मैनपावर है। करोड़ों करोड़ इंसान इस मुल्क में हैं जो अपनी श्रम शक्ति से इस देश को शक्तिशाली बना सकते हैं।

हमारा हिन्दुस्तान दुनिया का सब से धनी देश इस मामले में है कि प्राकृतिक सम्पदा या भगवान की दी हुई सम्पत्ति यहां पर है। तो क्या सरकार इस मैनपावर का इस्तेमाल इस दौलत को बढ़ाने में खर्च करेगी? आखिरी सवाल मेरा यह है कि क्या सरकार अपनी प्लानिंग मिनिस्टरी में या प्लानिंग बोर्ड में बेकारों की समस्या हल करने के लिए अलग सैल या अलग डिपार्टमेंट बनाने का विचार रखती है जिसके माध्यम से मालूम हो सके कि इस समय बेकारों की संख्या कितनी है और कितने बेकारों को काम दिया गया और कितने अभी बेकार हैं और भविष्य में उनके लिये सरकार क्या करेगी? अन्तिम सवाल यह है कि हमारा यह कहना है कि इस देश में यूनिवर्सिटी और डिग्री कालिजों की संख्या दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है। बी० ए० और एम० ए० पास करने के बाद

[श्री कल्पनाथ राय]

लड़के न घर के रह जाते हैं और न काम के लायक रह जाते हैं । उनके लिये कोई वोकेशनल या कोई पालिटेकनिक ट्रेनिंग नहीं है । मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि क्या वह विश्वविद्यालयों और डिग्री कालिजों की शिक्षा पर प्रतिबन्ध लगायेगी और हायर एजुकेशन के दरवाजे बंद करेगी ? और हाई स्कूल और इंटरमीडिएट पास करने के बाद हमारे देश के नवजवानों को ट्रेनिंग दी जा सके, पोलिटेक्निक की ट्रेनिंग दी जा सके, उनको इलेक्ट्रिशियन जैसे काम सिखाये जा सकें, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं ?

श्रीमन्, आखिरी सवाल मेरा यह है कि हमारा देश कृषि युग से निकल कर इंडस्ट्रियल ईरा में प्रवेश कर रहा है । आज हमारे देश में गांवों के अन्दर पंचवर्षीय योजना के माध्यम से विकास करने की बात कही जाती है, वहां हमारे देश को प्लान्ड इकोनोमी के माध्यम से एक शक्तिशाली और आधुनिक राष्ट्र बनाने और औद्योगिक विकास करने की बात भी कही जाती है। लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण भारी समस्यायें हल नहीं हो पा रही हैं । हमारी जनसंख्या दावानल की तरह से बढ़ती जा रही है। आजादी के बाद हमारी जनसंख्या में 37 करोड़ की वृद्धि हुई है । आप जानते हैं कि रूस की आबादी 24 करोड़ है और अमेरिका की आबादी 22 करोड़ है । हिन्दुस्तान में डेढ़ गुना अमेरिका और डेढ़ गुना रूस हम हर साल बढ़ाते जा रहे हैं। इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि इस बेकारी समस्या को हल करने के लिए क्या भारत सरकार जन संख्या पर नियंत्रण करने के लिए कोई ठोस और समय-बद्ध कार्यक्रम युद्धस्तर पर बनाने का कार्यक्रम बना रही है ?

श्री उपसभापति : अब आप समाप्त कीजिये ।

श्री कल्पनाथ राय : श्रीमन्, आखिरी सवाल मेरा यह है कि . . . (**व्यवधान**) उधर के माननीय सदस्य बीच में टोंट कस रहे हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि तीन वर्ष पूर्व जब इस देश में जनता पार्टी की सरकार थी तो उस वक्त हमारे देश में कितने बेकारों की संख्या में बढ़ोतरी हुई ? इनके प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई ने यह कहा था कि हम 10 वर्ष में बेकारी की समस्या को हल कर देंगे । क्या यह सही है कि सन् 1977 तक इस देश में बेकारों की संख्या एक करोड़ 38 लाख थी, लेकिन जनता पार्टी के राज्य में इनकी संख्या में 2 करोड़ 48 लाख की वृद्धि हुई । इन लोगों ने अपने शासन काल में, तीन वर्षों में कोई भी योजना देश को नहीं दी । मैं अपनी सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारी सरकार और हमारे प्लानिंग मिनिस्टर महोदय ने और हमारे केबिनेट ने बहुत ही कम समय में छठी पंचवर्षीय योजना का मसौदा देश के समक्ष प्रस्तुत किया है और यह कहा है कि देश के प्रखण्डों में प्रत्येक घर में एक आदमी को काम देंगे । छठी पंचवर्षीय योजना में यह लक्ष्य निर्धारित किया गया है । आप जानते है कि हमारे देश में औद्योगीकरण होने के कारण जो लोग लोहार का काम करते थे, जो कुम्हार का काम करते थे और जो कामगार का काम करते थे, वे सब शहरों में आ रहे हैं । भारी संख्या में लोग शहरों में आ रहे हैं । हमारे देश के गांवों में जो छोटी-छोटी जातियां थी जिनको पहले गांव में काम मिल जाता था, जैसे सुनार लोग थे, लोहार थे, गौड़ थे, जिनकी संख्या 114 या 116 थी, वे सब गांव छोड़कर शहरों की तरफ रोजगार की तलाश में आ रहे हैं । यही कारण है कि बड़े-बड़े शहरों में स्लम्स बढ़ते जा रहे हैं । इसलिए मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि हमारे शहरों में और गांवों में जो यह भगदड़ मची हुई है, इस समस्या को हल करने के लिये क्या आप कोई ठोस

और समयबद्ध कार्यक्रम बना रहें हैं? . . . (**व्यवधान**) मैं प्लानिंग मिनिस्टर साहब को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत ही कम समय में छठी पंचवर्षीय योजना का मसौदा देश के सामने प्रस्तुत किया है।

श्री उपसभापति : आपने यह बात कह दी है। आप अब दोहराइये नहीं।

श्री कल्पनाथ राय : मैं उनसे यह प्रार्थना करना चाहूंगा कि वे छठी पंचवर्षीय योजना में रुरल डेवलपमेन्ट का जो मसौदा तैयार कर रहे हैं उसमें क्या वे हमारे देश में पढ़े-लिखे ऐसे लोगों की लिस्ट भी बनाएंगे जो अभी तक बेकार हैं और उस लिस्ट को बना कर मैन-पावर का ठीक प्रकार से इस्तेमाल करने के लिए प्लानिंग कमीशन में कोई विचार करेंगे जिससे हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या हल हो सके और श्रीमती इंदिरा गांधी का यह सपना कि हमें इस देश को एक आधुनिक, शक्तिशाली और समाजवादी देश बनाना है, वह भी पूरा हो सके?

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : उपसभापति महोदय, मैं अपने मित्र कल्पनाथ राय जी को धन्यवाद देना चाहती हूं।

SHRI SYED SHAHABUDDIN (Bihar): Sir, the Rajya Sabha has been turned into a mutual appreciation society.

श्री लाडली मोहन निगम : (मध्य प्रदेश) अहोरूपम् अहो ध्वनि।

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : योजना मंत्री ने जो पढ़े-लिखे और बिना पढ़े-लिखे बेरोजगारों के लिये, उनकी रोजी के सम्बन्ध में जो योजना बनाई है उसके लिये माननीय सदस्य ने योजना मंत्री को धन्यवाद दिया है और उन्होंने सरकार से जिज्ञासा की है और वह यह जानना चाहते हैं कि आज देश में पढ़े-लिखे और बिना पढ़े-लिखे बेकारों की क्या संख्या है। तो मैं माननीय सदस्य को बतलाना चाहती हूं कि हमारे देश में कुल अन-इम्प्लाईड्स की संख्या 120 लाख है और ऐजूकेटेड अन-इम्प्लाईड्स की संख्या 35 लाख है और यह जो संख्या है इसके लिये माननीय सदस्य को यह मालूम होना चाहिए कि नेशनल सेम्पल सर्वे का जो 32वां राउंड आंफ सर्वे हुआ है, उसके आधार पर और जो इम्प्लाइमेंट एक्सचेंज हमारे सारे देश में कार्यरत है, उनके रजिस्टरों से फिगर्स लेकर यह सूचना एकत्र की गई है। जहां तक पढ़े लिखे लोगों का सवाल है, इनके अन्दर बेकारों की संख्या इस प्रकार है :—

इंजीनियरिंग डिग्री होल्डर्स	15700
इंजीनियरिंग डिप्लोमा होल्डर्स	65500
मेडिकल ग्रेजुएट्स	10100
डेंटल ग्रेजुएट्स	200
एग्रीकल्चर पोस्ट ग्रेजुएट्स/ ग्रेजुएट्स	8800
वेटरनरी ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स	700
एजुकेटड ग्रेजुएट्स	104200
आर्ट ग्रेजुएट्स	337900
आर्टस पोस्ट ग्रेजुएट्स	29900
साइंस ग्रेजुएट्स	154300
साइंस पोस्ट ग्रेजुएट्स	10600
कामर्स ग्रेजुएट्स	114400
कामर्स पोस्ट ग्रेजुएट्स	6200
अदर ग्रेजुएट्स	153600
टोटल ग्रेजुएट्स	1009100
मैट्रिक और हायर सेकेंडरी	2462900

इस तरह से उपसभापति जी, टोटल जो बेरोजगारों की संख्या आती है चाहे वे टेक्नीशियंस हों या नान टेक्नीशियंस

[श्रीमती राम दुलारी सिन्हा]

हों वह 34 लाख 72 हजार के करीब हैं जो कि 15.3 प्रतिशत है। मेरे पास इस समय यही फिगर्स एविलेबल है।

SHRI SHRIDHAR WASUDEO DHABE (Maharashtra): How many people were given employment in the last one year?

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : जरा सुना जाये और धीरज रखा जाये।

क्योंकि मैंने यहां आने से पहले कल्पनाथ राय जी से किसी तरह की बातें नहीं की है इसलिये उन्होंने जितने सवाल किये हैं वे सभी सवाल मुझे याद भी नहीं हैं। मैं उपसभापति जी से इस बात की इजाजत लेना चाहती हूं और उनसे आग्रह करना चाहती हूं कि अगर उन प्रश्नों को लिखित रूप से माननीय सदस्य कृपया मुझे दे दें तो मैं एक-एक करके उनके सभी प्रश्नों का जवाब दे दूंगी।

श्री उपसभापति : बाद में भेज दीजियेगा।

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : माननीय सदस्यों ने बढ़ती हुई बेरोजगारी की संख्या का जिक्र करते हुए कहा कि किस तरह से इस बेरोजगारी की समस्या को जो कि दुनिया के अन्दर भारतवर्ष में सबसे अधिक है काबू पाया जा सकता है। उन्होंने यह भी बतलाया इसे रोका जा सकता है। तो माननीय सदस्य को मालूम होना चाहिए कि उन्होंने रूस के सम्बन्ध में और अमेरिका के संबन्ध में फिगर्स तो नहीं दी लेकिन इस संबंध में कुछ कहने की कोशिश की। मैं माननीय सदस्य को यह बतलाना चाहती हूं और सारे सदन के सदस्यों को स्मरण दिलाना चाहती हूं कि हमारी पंचवर्षीय योजनायें जो कि पंडित जवाहर लाल नेहरू जी के नेतृत्व में कायम हुई तब से आज तक पांच पंचवर्षीय योजनायें पूरी हो चुकी हैं और छठी पंचवर्षीय योजना में हम जाने वाले हैं, उस ओर कदम ले जाने वाले हैं, तो इस दौरान हमने बड़े-बड़े उद्योग, बेसिक इंडस्ट्रीज और छोटे-छोटे उद्योग गांव से लकर शहरों तक, उद्योगों की बढ़ोत्तरी के सम्बन्ध में स्थापित किये जिनके नाम गिनाना मैं नहीं चाहती हूं इस बारे में सभी माननीय सदस्य जानते हैं बेरोजगारों को रोजगार से लैस करने के लिये हमारी योजनायें बनी थी और चल रही हैं लेकिन सेकिंड फाइव इयर प्लान के अन्दर जब हम बेसिक इंडस्ट्रीज को खड़ा करने लगे। अपने देश में लोहा और इस्पात की बहुलता के लिये उनके उत्पादन के लिये ताकि हम सेल्फ-रेलायमेन्ट हो जायें और इस बारे में खुद सक्षम हो जायें और दूसरे देशों से हमें मांगना न पड़े। इन जरूरियाती चीजों के निर्माण की प्रक्रिया में इम्पलायमेन्ट जनरेशन कुछ हद तक इस देश में हुआ। वैसे हमारे देश में कमी तो नहीं हुई लेकिन बढ़ नहीं सका। लेकिन अभी जो मैंने आंकड़े दिये हैं उनसे माननीय सदस्य को जानकारी हो गई है कि किस तरह से छठी पंचवर्षीय योजना के माध्यम से बढ़ती हुई बेरोजगारी की समस्या पर अंकुश लगाने जा रहे हैं। अभी हम बेरोजगारी पूरी तरह से नहीं मिटा सके लेकिन छठी पंचवर्षीय योजना के माध्यम से जो शुरू होने जा रही है, जहां बढ़ती हुई पापुलेशन... (**व्यवधान**)

श्री उपसभापति : यह तो हो चुका है।

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : माननीय सदस्य ने कहा, हम उनको याद दिलाना चाहते हैं कि किस तरह से फैमिली प्लानिंग के माध्यम से हम लोगों ने अपनी पापुलेशन पर अंकुश लगाने की कोशिश की थी और किस तरह से हमारे देश के विरोधी दलों ने उसके खिलाफ रात-दिन प्रचार कार्य किया और क्या कुछ हुआ और आज क्या हो रहा है, यह सब कुछ हम लोगों के सामने है। लेकिन इसके साथ-साथ मैं यह जरूर बताना चाहती हूं कि छठी पंचवर्षीय योजना में फैमिली प्लानिंग नहीं फैमिली वेलफेयर स्कीम कार्यरत हो रही है और इसके

बढ़ती हुयी आ बादी पर अंकुश लगाकर बढ़ती बेरोजगारी को कम करने की दिशा में बढ़ेंगे ।

SHRI SYED SHAHABUDDIN: I would like to know from the hon. State Minister the names of the opposition parties which are opposed to or have opposed the family planning programme.

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : इस स्कीम के माध्यम से . . .

SHRI SYED SHAHABUDDIN: She should not make a genaralised statement. She should not use the House for party propaganda.

श्री लाडली मोहन निगम : रामदुलारी जी आप तोता मत बनिये । कंठ से बोलिये, अपने पेट से बोलिये, तब अच्छा आप बोलेंगी ।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा: मैं तोता-मैना नहीं हूं—मैं जो हूं वह हूं । माननीय सदस्य राय साहब ने कहा कि क्या कोई कमेटी इस तरह की बनाने जा रहे हैं जिसने इन सब बातों का समाधान हो जाए मैं उनसे कहना चाहती हूं

that the Government is going to constitute a high level national guidance committee for self-employment and it will be constituted shortly.

SHRI V. GOPALSAMY (Tamil Nadu): Mr. Deputy Chairman, Sir, I may not agree with hon. Mr. Jha because this is the most serious problem of our country. We have had enough discussion on law and order problem of Gujarat and so on and so forth. (Interruptions). But this is a very serious problem. This spectre of unemployment is haunting the Indian youths and planners today. In spite of the huge investment under successive Plans, the number of unemployed is growing continuously. As the time at my disposal is very short I will not go into details, but we can take up the achievements plan-wise and also the employment-investment ratio which is the crux of the whole problem.

The first Plan created 7 million new employment opportunities. The employment investment ratio was 1:6057. That means for creating one new opening of employment an amount of Rs. 6057 was required to be invested in the economy during that period. In the Second Plan 10 million new employment opportunities were created. The employment-investment ratio was 1:8432, that is 39 per cent higher than that in the First Plan. This trend should be noted. Again the Third. Plan generated employment for 14.5 millions, the ratio being 1:754-5, whicn is about 10 per cent lower than the one in the Second Plan. Now the trend declined and it was followed by the three annual plans. The Third Plan was followed by three annual plans that created 11 million new employment opportunities. The ratio was 1:5754, lower than the one in the Third Plan, but in the Fourth Plan, though 185 million new employment opportunities were created, the ratio was 1.6357. Again the trend was on the increase because it was higher than the previous one. The Fifth Plan created new jobs of 22 millions, the ratio being 1:8400, 32 per cent higher than the ratio in the Fourth Ran. The trend of this ratio is the main problem because of the law of diminishing returns and the rising costs, which is going to be the single biggest obstacle in the way of progress of the country and humanity as a whole. That was the view of David Ricardo, the greatest economist. All our efforts at providing jobs for alt are being thwarted by this eternal law of diminishing returns.

Again, coming to the Sixth Plan, it hopes to create 30 million new jobs. Already we have a backlog of 22 million. There will be 32 million new entrants. So 54 million jobs are required. And We aim at creating 30 million new jobs. The ratio would be, it is estimated, 1 : 9000 for the Sixth Plan. So what should be the future

[Shri V. Gopalsamy]

line of action? So far we have taken all possible steps, but what should be the future line of action?

SHRI N. K. P. SALVE (Maharashtra) : What will be the ratio?

SHRI V. GOPALSAMY: It is estimated to be 1 : 9000.

SHRI KRISHNA CHANDRA PANT (Uttar Pradesh): How many jobs it will create?

SHRI V. GOPALSAMY: Thirty million are expected to be created. Already we have got a backlog of 22 million. There will be 32 million new entrants. So the total will be 54 million. Thirty million jobs are expected to be created. So what should be the future line of action? So far we have been concentrating on increasing production and investment from Plan to Plan, leaving the employment to find its own level. That has been our policy so far. This is the laissez-faire policy of the classical economists. With this policy, we have not made any dent on the employment problem. So what should be done? This non-intervention attitude should be given up and we should frame a specific employment policy at the official level itself.

Sir, it is generally believed that it is the capital which creates employment. But, Sir, the German experience shows a different path. After the Great Depression of 1929 and 1933, the Germans followed a different policy. Hitler at that time followed a different policy. We may hate Hitler; his very name brings distaste; we may hate him because of his war mania; but he announced a different employment policy in 1933. At that time, unemployment exceeded 6 million in Germany. That was the greatest problem faced by Germany. Hitler said: "It is not the capital which creates the work; but the work creates the capital". And he also said: "If the unemployed are put to work that would increase production, if not significantly at least marginally." So that would increase the capital promotion, savings, improve the living standards and the whole economic process. Of course, they found it difficult at first. They saw the tax revenues declining and the expenditure on subsidies mounting. But after two years, when the employment situation improved, the trend was reversed. Not only that, Sir, he levied stiff taxes on those employers who did not absorb the unemployed even though they had huge returns.

So we should have a thorough policy. The employment policy should be enunciated by the Government. The general economic principle is that a country should liberally use its abundant factors in production and at the same time it should economise on the use of scarce factors. In India, labour is an abundant factor; capital is a scarce factor. That is why the interest we pay for the capital is high. The growing unemployment shows that labour is an abundant factor. This Government should enunciate this policy in clear-cut terms regarding the use of capital as a substitute for labour. This is the main thing. The Government should enunciate this policy. There is no necessity for the LIC, the railways; the commercial banks or Air India to utilise electronic computers. Of course, the export industries, some defence industries may require electronic computers. Sir, for LIC it was estimated that 3.7 persons were required for handling one thousand policies some years back Now it is estimated that 1.6 persons are required to handle one thousand policies. The public sector undertakings, LIC, the Indian Railways, the commercial banks etc. should be given directions that they should not substitute capital for labour. They should not utilise electronic computers. Another serious problem. is regarding skilled labour. The serious problem there is job racketing by unscrupulous elements. In our country this job racketing is going

on. This is a very serious problem. I would request the hon. Minister to have a consultation with the Law Ministry and bring out a comprehensive legislation to stop this menace.

So, Sir, these are all the problems. This is a very difficult subject and I cannot put forth my views within ten or fifteen minutes. Anyhow, I hope that all the other Members will also express their views. The Government should enunciate its employment policy. Of course, the Budget was a very brilliant budget but, at the same time, I would say that regarding tackling of unemployment we have not devoted our attention towards that problem. The Budget Speech—I am very sorry to say that has no* made any reference to this problem. So I would like to know from the hon. Minister whether the Government will enunciate such a policy regarding the use of capital as a substitute for labour and also its employment policy for the country.

SHRIMATI RAM DULARI SINHA: "Sir, I would like to extend my thanks to the honourable and learned Member. He has suggested so many things. But, Sir, I would like *to* tell the hon-Member that we are not here to discuss economics and we are not here to learn or teach economics. We are just discussing the subject arising out of this Calling-Attention.

SHRI V. GOPALSAMY: Madam, I am neither a student nor a teacher. I am a Member of this Parliament. You have not understood what I said.

SHRIMATI RAM DULARI SINHA: I have understood it well.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please note his suggestions for your gui--dance.

SHRIMATI RAM DULARI SINHA: I have noted all his suggestions. Sir, and they will be replied to later.

SHRI V. GOPALSAMY: Madam, you are just reading out a prepared reply which you are having in your hand. 2025 RS—8.

SHRIMATI RAM DULARI SINHA: First let me reply.

SHRI N. K. P. SALVE; Sir, implicit in his question is an assumption, when he spoke of employment-investment ratio, that the investment contemplated in the Plan is not adequate to meet the employment. Now, if it is 34 million employees to be taken according to the figures he has given, the investment should be 30,600, and if it is taking the backlog, it is 48,600. For 54 million the investment is 48,600. Therefore, the Plan already takes in that much investment before they create that much employment.

SHRI V.
I am thankful to Mr. Salve. That is what I have said: we should have an enlightened discussion on the subject.

SHRI KRISHNA CHANDRA PANT: Sir, may I say that the questions which have been put by my friend are very important and they really go to the heart of the matter? He is asking the Government to come out with an employment policy and its whole approach to the problem. He has put forward a certain approach. Now this question, I would beg of you, requires some answer because the whole country is interested in it. What is the whole approach of the Government? He has given very specific figures. To this there must be a reaction.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The Minister has already said this is the approach to unemployment.

SHRI KRISHNA CHANDRA PANT; No, Sir. I am afraid, with all respect, that even you have not followed him fully. We must acknowledge that he has given a point _ of view which many of us may share. The Government can say "We do not share this point of view." That is perfectly all right. But the questions cannot be ignored and cannot be put on the shelf. If there is no adequate answer, I would say, there

[Shri Krishna Chandra Pant] should be a special discussion en the subject. It is very important. I do not think his question should be dealt with in this manner.

SHRIMATI RAM DULARI SINHA: First let me reply, Sir. The estimate of generation of employment in the Sixth Plan is based on employment output and investment relation. Due to inflalation, more investment is now needed to generate the same amount of employment. So the Government have examined all the aspects and have worked out the employment strategy.

SHRI NARASINGHA PRASAD NANDA (Orissa): Sir ... *(Interruptions)*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is a big question. It cannot be replied fully; nor can you put all the questions.

SHRI NARASINGHA PRASAD NANDA; Sir, this Calling Attention raises a very basic problem, the problem of unemployment in the country. Sir, I am personally of the opinion that unemployment is inherent in the present system. While you go on generating some employment, giving some employment opportunities, those opportunities are so small compared with the growth of unemployment that they will absorb a minimal percentage of the growing unemployment. And that is how you go on adding to the number of the unemployed people in this country. Since we are confining ourselves to the Calling Attention subject and we are not having a debate on the problem of unemployment at length, I will now give you an analysis of the tendencies that we have noticed in our economy, showing as to how efforts have been made for generating employment, but in spite of those efforts, unemployment has been growing persistently. As I said, that is because of the very inherent defect in the 6ystem. *1* do not blame any individual I for that, when the system itself is defective. Unless the Government thinks of some radical measures to effect structural changes in the economy of this country to bring about basic socio-economic: transformation, instead of raising slogans in the name of A, B or C...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You spell it.

SHRI NARASINGHA PRASAD NANDA; I will spell it so that she can reply, if you have patience...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have patience; there is no lack of that. But there is the question of time.

SHRI NARASINGHA PRASAD' NANDA; The job opportunities created from time to time are not sufficient enough to absorb the growing unemployment in this country. And to piove this point, 1 will not take you through the entire statistics furnished by the Government

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That hardly requires any proof. It is obvious.

SHRI NARASINGHA PRASAD NAIsDA: Only one set of figures I will quote in support of my conten tion. As per the live registers of the job seekers maintained by the em ployment exchanges—which are considered to be authentic documents —the number of the unemployed went from 13.98 million at the end of August, 1979 to 15.64 million at the end of August, 1980. So there is an increase of 11.9 per cent. Now,, what was the absorption of the un employed people during this one year? According to the Government statistics, 5.3 per cent people were absorbed in the public sector and 3.3 per cent in the private: sector and there was a gap of 4.4 per cent of the people who could not be absorbed in the employment generated in the country. That means for one year only there was a rise in the number of the unemployed by 4.4 per cent.

Like this, if you go on scrutinising, *you* will find that the unemployed people are growing in numbers. Now, Sir, so far we have with us only the numbers of the people unemployed in the organised sector. And even •those statistics which are available to us through the National Sample Survey are defective. But you find that there is a big unorganised sector in this country— a sector of which neither the employment exchanges maintain any registers nor is there any authentic record with the Government to show the number of people unemployed in the unorganised sector in this country. There is also the problem of half-employment, one-fourth employment and part-time employment. This problem of the various sections of the people is there. I agree with Mr. Gopalsamy though not for the same reasons stated by him. I would like the Government of India to have an employment policy because you will kindly find from the Economic Survey which was distributed amongst the Members of Parliament that it absolutely does not deal with this problem at all. This problem of the gigantic proportion in which it is increasing in this country, the Survey does not deal with. There is a casual reference to employment in the organised sector, but there is absolutely no reference to the unorganised sector. There is no reference to the jobs that are to be created in the course of the next year. There is no reference to the number of persons likely to be absorbed in the course of the next year. Now they have come forward with a new concept of 'standard person-year'. I would respectfully submit before you Sir, that this is a statistical jugglery. The idea of creation of additional 3.4 crores standard person-year is purely a statistical jugglery. This does not take you anywhere. This is meant more to conceal than to reveal the truth of the gigantic dimension of the problem.

Sir, I would like to know from the hon. Minister this. I could give an Economic Policy if I were in her position or in the position of Mr. N. D. Tiwari, the Minister of Planning. I have something in my mind, but I cannot discuss it here while putting a few questions on the Calling Attention. If the hon. Minister calls me and wants to discuss it with me, certainly, I have my idea and I can discuss it with her. You wanted me to say something about it. But this is not the occasion That will take some time. After all, this is not a small thing that in one word or in one sentence I can let out my ideas about creation or generation of employment opportunities.

Sir, I will put a few questions here. Number one, what is the latest figure of employment in the organised sector, both public and private? Number two, has any study been conducted in the unorganised sector to ascertain the number of persons employed in that sector? Number three, what is the latest figure on the live register of the Employment Exchanges? I will give my own figures.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thosa figures have been given.

SHRI NARASINGHA PRASAD NANDA: The latest figure has not been given. You do not find it even in the Economic Survey.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: '"^She has given it in the House.

""SHRI NARASINGHA PRASAD NANDA: 1 have seen the statement.

' MR. DEPUTY CHAIRMAN: She gave them later on.

SHRI NARASINGHA PRASAD NANDA; No, Sir. Those figures related to the earlier year.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Go on repeating the same thing.

SHRI NARASINGHA PRASAD NANDA: She will repeat the old figures.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You put the question. She will not iepeat.

SHRI NARASINGHA PRASAD NANDA: Then, I would like to know the rate of increase in unemployment which is another question. I want the annual increase of the unemployed and the rate of absorption every year, and the gap—the unemployed who are not absorbed in the course of that year. Then I would like to know how many unemployed are being carried forward from year to year. And lastly, the important question that I would like to ask is whether they would be prepared to conduct a special study particularly of the unorganised sector, about Which friends quote different figures, I attended a seminar where it was said that the present number of unemployed in this country is 60 million. Some people say 22 million, some people say 30 million...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That will do.

SHRI NARASINGHA PRASAD NANDA: Please listen. Some people say 32 million. In one seminar I was told that it was 60 million. Why should not the Government come forward with some authentic statistics which will give an indication of the dimension of this problem? Is she prepared to do that?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That will do. Yes, the hon. Minister.

SHRIMATI RAM DULARI SINHA: I am thankful to the hon. Member for giving me so many suggestions. Sir, the unemployment position...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No suggestion. He only described the dimension of unemployment and wanted to know the position of unemployment. He has not given any suggestion. He has only given the dimension of unemployment.

SHRIMATj RAM DULARI SINHA: The unemployment posttion is certainly causing concern. That I have already stated. A lasting solution can be found within the frame work of a rapid employment oriented economic growth. However, in the short term suitable measures should be undertaken to help the weaker sections. I haye already referred to the measures-in my opening statement,

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That will do. Shri Nigam.

श्री लाडली मोहन निगम : उपसभापति जी, अच्छा होता इस मसले पर हम लोग विस्तार से चर्चा कर सकते क्योंकि बेकारी की समस्या को मैं देश के उत्थान के साथ सम्बद्ध समझता हूं। जहां तक सवाल है मंत्री जी के बयान का, उस से कुछ संतोषजनक निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। मैं एक बात की तरफ तवज्जह जरूर दिलाना चाहूंगा कि क्या मंत्री जी को मालूम है कि अब तक हिन्दुस्तान में जो भी पांच पंचवर्षीय योजनाएं हो चुकी हैं उन के तहत करीब-करीब 19 मिलियन, मतलब 1 करोड़ 90 लाख, रोजगार आप लोगों के लिए खोल सके हैं ? जब मैं 1 करोड़ 90 लाख की बात करता हूं तो उस में निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों ही शामिल हैं। आप का मंसूबा है कि छठवें मंसूबे के अन्दर आप करीब-करीब 3 करोड़ 40 लाख लोगों को नया रोजगार देंगे। खैर, अगर मान लूं कि आप का मंसूबा पूरा हो जायेगा, जिस के पूरा होने की कोई संभावना नहीं है,—पिछली पांच योजनाओं में 1 करोड़ 90 लाख लोगों को काम मिला और अब आप छलांग लगा रहे हैं—तो 3 करोड़ 40 लाख लोगों को रोजगार देंगे। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो रफ्तार है उस का तखमीना लगा लिया जाये तो मुझे ऐसा लगता है कि करीब-करीब 75 वर्षों के बाद इस मुल्क की बेकारी की समस्या हल होगी। जिस तरह इनसानों की नसबन्दी कर दी गयी है, आज अगर आप के पास कोई ऐसा औजार हो जो बेकारों की नसबन्दी कर दे तब जाकर जो मौजूदा बेकारों की संख्या है उस को आप 75 वर्षों में रोजगार दे सकेंगे। यह बात बड़ी लुभावनी है। एक आदमी बेकार है। जब सरकार की तरफ से घोषणा होती है कि 3

करोड़ 40 लाख लोगों को काम मिलेगा तो वह सोचता है कि इन 3 करोड़ 40 लाख लोगों में मेरा भी तो नम्बर आयेगा। लेकिन सरकार और उसकी पार्टी के लोग इतने चालाक हैं, वह जानते हैं कि 75 वर्ष तक का प्रोग्राम दे दो, 75 वर्ष तक न वह रहेंगे जिन्होंने वायदा किया है, न 75 वर्ष तक वह जिन्दा रहेंगे जिनको रोजगार चाहिए। तो यह सब तखमीना है जिसका फैसला नहीं होगा, यह फैसला तो कबरिस्तान में जाकर होगा। मैं कहना चाहता हूं कि आज हिन्दुस्तान की हालत यह है कि कोई भी बेकारी को दूर करने की इनके पास योजना नहीं है। बेकारी को दूर करने का सवाल ही नहीं है। अगर हिन्दुस्तान में बेकारी खत्म हो जाएगी तो जिस अनुपात से हमारा उत्पादन बढ़ा है उसकी खपत होना शुरू हो जाएगी। अगर खपत होना शुरू हो जाएगी तो बेकारी दूर हो जाएगी। तो ये बेकारी को बनाये रखना चाहते हैं। . . . (व्यवधान)

SHRI BIPINPAL DAS (Assam): What you are saying is a contradiction in terms.

SHRI KRISHNA CHANDRA PANT He is your old colleague.

श्री लाडली मोहन निगम : वही मैं निवेदन कर रहा हूं। बेकारी का सिलसिला पैदावार के साथ जुड़ा हुआ है। अब सवाल यह है कि हिन्दुस्तान में जितने भी मंसूबे बन रहे हैं, ये जो भीमकाय योजना आ रही है, यह सब पूंजी आधारित योजना है, श्रम आधारित योजना नहीं है। जब तक हिन्दुस्तान की सरकार कोई भी श्रम आधारित योजनाओं पर अपना मंसूबा नहीं बनाती तब तक आप बेकारी की समस्या हल नहीं कर सकते।

इसी के साथ जुड़ी दूसरी चीज यह है कि कितने लोग बेकार हैं इस देश में इसका पता नहीं है। क्या मंत्री महोदय इसकी पहल करना चाहेंगे कि यह देश को पता लग जाए कि हम कितने नंगे हैं और सरकार किस तरह से मुल्क के नंगेपन को बढ़ा रही है? क्या आप पहल करेंगे कि ग्राम पंचायतों में आपका एक रजिस्टर हो जहां बेकारी का इंदराज हम कर सकें, म्युनिसिपैलिटी में भी ऐसा रजिस्टर हो और जहां ग्राम पंचायतें नहीं है वहां पटवारी के पास खाता हो और यह बता सके कि कितने बेकार है? जब तक हम इसे बागू नहीं करेंगे तब तक इसका पता नहीं लगा सकते। . . .

(व्यवधान)

श्री उपसभापति : बेकारी कैसे दूर होगी, यह भी कहिये। यह पता लगाइये ये तो सभी लोग कह रहे हैं। बेकारी कितनी है, यह सब पूछ चुके हैं। क्या करना है, बेकारी इस तरीके से दूर की जाए, ऐसा भी कहिये। please give some suggestions for a solution to the problem.

श्री लाडली मोहन निगम : अगर आपको डाइमेंशन का पता नहीं है तो आप क्या हल निकाल सकेंगे? . . . (व्यवधान)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Nobody is giving any suggestions. Everybody is only describing the dimensions of unemployment. Please give some suggestions. Nandaji put a question but she could not reply to that question. So, please give some suggestions.

श्री लाडली मोहन निगम : मैं आपसे निवेदन करूंगा कि . . . (व्यवधान)

श्री उपसभापति : जो प्रश्न नये हों, जिनके आंकड़े दिये जा सकें, उनके बारे में पूछें। यह मेरा निवेदन है। जो आंकड़े नहीं हैं उनको पूछते हैं। कुछ सुझाव दीजिए कि किस तरह से बेकारी को दूर किया जाए क्योंकि कालिंग अटेंशन इतने सदस्यों ने लिखकर दिया। 50 आदमियों ने लिखकर दिया, तो मंजूर हुआ। इसके लिए समझ चाहिए। . . . (व्यवधान)

श्री लाडली मोहन निगम : श्रीमन् मैं उन चीजों पर आ रहा हूं। एक तरफ मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे बेकारी बनाई जा रही है एक तरफ सरकार का जो लेखा-जोखा, बजट

[श्री लाडली मोहन निगम]

का हुआ, जो उन्होंने पेश किया उसमें माचिस पर इस तरीके से टैक्स, कस्टम ड्यूटी का मामला किया है कि उसके चलते दक्षिण भारत में हाथ से बनाने वाले माचिस के कारखाने बन्द होने की स्थिति में आ गये हैं तो और बेकारी बढ़ी। तो मैं यह बता रहा था कि यह विरोधाभास है। जो भी थोड़ा बहुत काम मिलता था वह भी खत्म हो गया। मेरी सूचना है कि 80 लाख जो हाथ से काम करते थे वह आज बेकारी के शिकार हैं। तो मैं चाहता हूं कि इस पर आप विचार करें ।

साथ ही साथ आपने कहा कि सुझाव के लिए, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर हिन्दुस्तान के ग्रामीण इलाके की बेकारी दूर करनी है तो आपको निश्चयात्मक इस बात के लिए कदम उठाने पड़ेंगे। अगर आप फर्क रखते हैं तो गांवों में कोई भी बड़े उद्योग नहीं लगेंगे छोटे उद्योग लगेंगे । तो आपको यह करना पड़ेगा कि जो चीजें छोटे उद्योग में पैदा होती हैं वह बड़े उद्योग पैदा नहीं करेंगे चाहे वह साबुन हो, या दूसरी चीज हों । इसकी आपको तालिका बना लेनी चाहिए।

1 P.M. जिस तरह से सेक्टर बांटे इस के भी सैक्टर बांटे। श्रम लगेगा तो पूंजी कम लगेगी और लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिलेगा। एक सुझाव यह है और दूसरा सुझाव यह है कि बड़े पैमाने पर इस मुल्क में आप के मनसूबे सिंचाई के साथ जुड़े हुए हैं तो क्या आपकी सरकार ग्रामीण बेकारी को दूर करने के लिए कोई ऐसी योजना बनाने जा रही है जिससे देश में बहुत बड़े पैमाने पर एक अन्न सेना और भूमि सेना बन सके जो सिंचाई के साधनों में ज्यादा श्रम से काम कर सके । अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं इतना कह सकता हूं कि अगर देश में यह फैसला कर दिया जाये कि देश की हर प्यासी धरती को पानी मिलना है तो इस में 30–35 करोड़ रुपया लगेगा । एक बात मत भूलिये जिस रोज हम यह मंसूबा बना लेंगे कि सारी धरती को पानी पिलाना है तो जहां तक मैंने हिसाब लगाया है मुझे ऐसा लगता है कि करीब तीन करोड़ लोगों को रोजगार देना पड़ेगा। तीन करोड़ इंसान को उन को रोजगार देगें जो हाथ से काम करेंगे । इस के बाद इसकी बनाने वाले ड्राफ्टमैन, नक्शा बनाने वाले, इंजीनियर, मिस्त्री आदि हैं इनकी संख्या अलग है । अगर देश में सिर्फ यही एक योजना लागू कर दी जाये तो कम से कम 11 लाख इंजीनियर, मिस्त्री, नक्शा बनाने वाले हमको चाहिए । जबकि हिन्दुस्तान के सारे जितने इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय हैं उन की संख्या निकाल दी जाये तब भी पूरा नहीं होगी । मेरा कहना है कि तवज्जो इस चीज पर देनी है कि किस तरीके से हिंदुस्तान में हम ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर प्रदान कर सकते हैं । रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए दो तरीके मैं आपके सामने रखना चाहता हूं । एक तो तात्कालिक कदम है । इसके लिए मैंने बताया कि क्षेत्र तय करने पड़ेंगे। संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र । असंगठित क्षेत्रों में जो आम सामान उत्पादन का माल बनता है उसको बड़ा संगठित क्षेत्र न बनाये । दूसरे तात्कालिक रूप में आप यह भी कर सकते हैं कि इस देश में बहुत बेकारी है इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि एक खानदान के 10 आदमी को रोजगार हो । एक खानदान ऐसा है जो भूखों मर रहा है । यह काम हम अपनी ही सरकार से शुरू कर सकते हैं । यह भी है कि मियां-बीवी दोनों को ही सरकारी नौकरी मिलती है । इस में यह भी है कि बीवी की नौकरी और मियां की नौकरी एक जगह होनी चाहिए । अगर एक ही जगह होनी है तो किसी दूसरे आदमी का हक मारा जाता है । जो पिछड़े लोग हैं , मध्य प्रदेश की बात है मैं कह सकता

हूं कि कम से कम 12–14 सौ अफसर ऐसे हैं जिनकी पत्नियां नौकरी कर रही हैं । 10-11 बजे पति देव चले गये दफ्तर, तो वह कहीं स्कूल में चली गई । भोपाल शहर में इतने स्कूल नहीं हैं इस लिए उन को नौकरी दी गइ है किसी गांव में या किसी दूसरे जिले में और तनख्वाह यहां भोपाल से लेंगे । क्यों नहीं ऐसा कानून बनाते, ऐसा काम करते कि जब तक देश में समुचित रोजगार नहीं मिल जाता तब तक सरकारी नौकरी में मियां-बीबी में से एक को नौकरी मिलेगी। (व्यवधान) आज तक यह परम्परा रही है कि आदमी कमाता है और औरत खाती है । आज दोनों कमाते हैं और खाते हैं। मियां-बीबी आज दोनों सरकारी नौकरी कर रहे हैं। उन में महिला अगर नौकरी करना चाहे तो वह कर सकती है ...

श्री उपसभापति : उन से पूछ लीजिये ।

श्री लाडली मोहन निगम : मेरा सुझाव है ... (व्यवधान)

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : एम० पीज० के लिये नहीं कह रहे हैं ।

श्री सभापति : एम० पीज० के लिए भी किया जाये । (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र मोहन (उत्तर प्रदेश) : यह लाडली मोहन निगम जी की प्राब्लम नहीं है । (व्यवधान)

SHRIMATI HAMIDA HABIBUL-LAH (Uttar Pradesh): Why are you encouraging laziness among men?

श्री लाडली मोहन निगम : ख्वाबगाह में औरतों की मेहनत काम आती है । उस से पुरुष काहिल नहीं होता । वह सबसे ज्यादा चेतन रहता है । जब तक नौकरियां नहीं हैं तब तक दोनों में से एक को नौकरी मिलनी चाहिए । और तीसरी चीज इस में जुड़ी हुई यह है कि हिन्दुस्तान में अधिकांश लोग खेती करते हैं और यह प्रश्न खेती से भी जुड़ा हुआ है ... (व्यवधान) । हमारे मुल्क में कुछ लोग ऐसे हैं और मेरा ख्याल है अधिकांश लोग ऐसे हैं जो अन्य धन्धा भी करते हैं, नौकरी भी करते हैं और गांवों में उन के पास खेती भी है, जमीन का पट्टा भी है। मेरा कहना यह है कि एक आदमी एक ही धंधा करे और मियां-बीबी में से एक ही आदमी सरकारी नौकरी में रहे ... (व्यवधान) । कृष्णा साहब आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं आपकी पत्नियों को हक देना चाहता हूं । हम चाहते हैं कि कि मियां तो घर में काम करे, चौका-बर्तन साफ करे और पत्नी दफ्तर में काम करे । अभी तो एक स्थिति है कि अगर मिया-बीबी दोनों सरकारी नौकरी में हैं तो उनको एक ही जगह पर रखना पड़ता है। जब मियां-बीबी दोनों एक ही जगह पर रहेंगे तो पोपुलेशन आप कैसे कम करेंगे । आप नस-बंदी की बात करते हैं । जब मियां-बीबी दोनों एक स्थान पर रहेंगे तो आप आबाद की समस्या को कैसे हल कर सकते हैं) ।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Do not come into conflict with ladies. Please conclude.

SHRIMATI HAMIDA HABIBUL-LAH: Are you advocating more employment or more unemployment?.

श्री लाडली मोहन निगम : हम तो आपके अधिकारों को बढ़ाना चाहते हैं ।

श्री उपसभापति : आप महिलाओं के बारे में कुछ मत कहिए ।

श्री लाडली मोहन निगम : हमारे देश में महिलायें खेतों में काम करती हैं । पुरुष भी खेती में काम करते हैं। मेरा कहना यह है कि जो लोग नौकरी करते हैं उन को एक ही धंधे में रहना चाहिए । वे लोग नौकरी भी करें और खेती भी करें यह नहीं होना चाहिए । अगर आप ऐसा करेंगे कि एक आदमी एक

[श्री लाडली मोहन निगम]

ही धन्धा करे तो इस से बेकारी की समस्या को हल करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। मैं चाहता हूं कि आप बेकारों का एक राष्ट्रीय रजिस्टर बनाइये।

SHRI M. R. KRISHNA (Andhra Pradesh): He is talking about sophisticated ladies only, Sir.

श्री उपसभापति : आप क्यों परेशान हो रहे हैं, आपकी पत्नियों के बारे में वे नहीं बोल रहे हैं।

श्री लाडली मोहन निगम : आपको बेकारों का राष्ट्रीय रजिस्टर बनाना चाहिए। जब तक बेकारों का एक राष्ट्रीय रजिस्टर नहीं बनाएंगे तब तक आप इस समस्या को हल नहीं कर सकते हैं। मैंने ये तीन सुझाव दिये हैं और मैं चाहता हूं कि ग्राम पंचायत के स्तर पर और म्युनिसिपल कमेटी के स्तर पर आप बेकारों का एक राष्ट्रीय रजिस्टर बनाइये। उसके साथ ही आप भूमि सेना और अन्य सेना भी बनाइये। अगर आप ऐसा करेंगे तो ग्रामीण स्तर पर बेकारी दूर करने में मदद मिलेगी। इसके साथ-साथ प्रत्येक क्षेत्र में सामान्य उपयोग की जो जरूरी चीजें हैं उन सब का उत्पादन हाथों से होना चाहिए और हाथों के श्रम से उनको बनाया जाना चाहिए मशीन से उनको नहीं बनाया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि अगर आप ऐसा करेंगे तो इस समस्या को हल किया जा सकता है। सरकारी नौकरियों में मियां-बीवी दोनों को नहीं लगाया जाना चाहिए। या तो बीवी सरकारी नौकरी में होनी चाहिए या मियां को सरकारी नौकरी में होना चाहिए। एक को ही सरकारी नौकरी में होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि नये उद्योगों और अवसरों के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों को रोजगार देने की तरफ आप ध्यान दें।

श्रीमती [रामदुलारी सिन्हा : श्रीमन्, जहां तक माननीय सदस्य ने पुरुष और नारी के संबंधों के बारे में कहा है उसके संबंध में मैं एक ही शब्द कहना चाहती हूं—

"मैं बुरा कहती नहीं कि यह पुरुष
पितृ समाज है,
नारियां हैं देवियां तो पुरुष उसका
साज है।"

श्री लाडली मोहन निगम : श्रीमन्, नारी के बारे में तो यह कहा गया है कि 'आंचल में है दूध, आंखों में है पानी' इस बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा है। इस कारण से देश दूषित हो रहा है और टूटता जा रहा है।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : यह गुलामी के परियड की कविता है। कुछ मैंने भी पढ़ा है और कुछ मैं भी जानती हूं। गांधी और नेहरू के नेतृत्व में भारत की नारियां अबला से सबला हो चुकी हैं।

श्री लाडली मोहन निगम : मैं तो आप से छोटा हूं।

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : उपसभापति महोदय, अगर माननीय सदस्य के कहने का मतलब पुरुष और नारी को इक्वेल इम्प्लायमेन्ट देने से है, इक्वेल मिनिमम वेजज देने से है इक्वेल रिम्यूनरेशन देने से है तो हमारी सरकार इसमें बिलकुल कार्यरत है, श्रम विभाग इसको लागू करने के लिए पूरी चेष्टा करता आया है और कर भी रहा है। मैं... (व्यवधान)

श्री लाडली मोहन निगम : उपसभापति महोदय, आज इस देश में आधा वाक्य चल रहा है 'पराधीन सपनों सुख नाहीं'। लेकिन जब सती जल गई तो सती की मां ने जो कहा था वह इस तरह था :

'केहि विध रची नारी जग माही,
पराधीन सपनों सुख नाहीं।।'

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :

"हम चंडी हैं, हम काली हैं, हम
गजब ढाहने वाली हैं,
अब हटो न रोको तुम हमको,
हम मातृभूमि की प्यारी हैं।"

(व्यवधान)

उपसभापति महोदय, जहां तक बढ़ती आबादी पर अंकुश लगाने के सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने कहा है तो मैं उनको सुझाव देना चाहती हूं कि सारे देश के जितने भी पार्लियामेंट के मेम्बरान हैं, उनके साथ साथ वे भी इसमें हमारे साथ सहयोग करें। बढ़ती हुई आबादी पर अंकुश लगाने के लिये उन्होंने एक शब्द नसबंदी का इस्तेमाल किया पर मैं उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहती। पर इतना जरूर कहना चाहती हूं कि इस बढ़ती हुई आबादी पर जब तक हम अंकुश नहीं लगायेंगे तब तक इस बढ़ती हुई बेरोजगारी की समस्या का हम समाधान नहीं कर पायेंगे। इसलिये मेरा माननीय सदस्य से आग्रह है कि हमारे इस अभियान में कम से कम आज से सहयोग देना शुरू कर दें।

श्री लाडली मोहन निगम : सहयोग दे रहा हूं।...(**व्यवधान**)

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : जहां तक माननीय सदस्य...(**व्यवधान**)... ने बेकारी को खत्म करने से संबंधित योजनाओं पर छींटाकशी की है तो मैं सारे सदन को बताना चाहती हूं कि इंदिरा जी के नेतृत्व में जितनी भी श्रम योजनायें चलाई गई हैं वे सब बेरोजगारी को खत्म करने से संबंधित हैं।

I havo already stated in my previous statement Sir, that when it is set up during this Plan it will play a dynamic role. Employment Exchanges will be revamped and will assist the District Councils that will help the rural unemployed.

श्रीमती कनक मुखर्जी (पश्चिमी बंगाल): इनकी कविता सुनकर मैं भी एक कविता सुनाना चाहती हूं।...(**व्यवधान**)... मेरी कविता सुन लीजिये। (**व्यवधान**)

श्री उपसभापति : सदन की कार्यवाही 2 बज कर 15 मिनट तक के लिए स्थगित की जाती है।

The House then adjourned for lunch at twelve minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at sixteen minutes past two of the clock, Mr. Deputy Chairman in Chair.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Bhupesh Gupta.

SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal): May I start by asking the Government as to what would be its reaction if I were to make a suggestion that the Central Government should have a scheme for unemployment relief such as they have in Kerala? The Central Government should also do the same. I just put it in the beginning because towards the end of the discussion some little things should at least emerge.

Now, as far as the problem is concerned, I do not know what really it is that they are going to achieve by this discussion except ventilating our very well-known positions over the years. When the First Five Year Plan was drafted, in fact when the plan frame was under consideration, it was pointed out that at the end of the First Five Year Plan the unemployment in the country was of the order of, according to the live register, 3.3 million. Today, at the end of the beginning of the Sixth Five Year Plan or whatever you call it, we have this figure of around 16 million. This is only indicative of the growth of un-employment. But by no means it gives the correct picture because the Employment Exchange figures are always partial and they give an underestimate. Now, according to some economists in the country, taking the unemployed persons as well as the

[Shri Rhupesh Gupta] under-employed persons, that is to say, the cases of disguised employment, the figure would be of the order of 50 to 60 million and no less. Whatever the Employment Exchange figures might show. Many villagers do not .go to the Employment Exchanges and so on. Apart from that, there are other considerations also which do not give us the complete figure through the Employment Exchanges. Now, the position is this. With every Five-Year Plan the unemployment is show-balling and no Plan has been able to check it. In the past, at least better statements were made than the one that has been made as to how the unemployment could be checked and curbed. That is the position. From the Fourth Five Year Plan, you will find that there is no serious attempt to assess the employment situation in the country. In the Second Five Year Plan, I remember, Sir, there was a very seriou? attempt to assess the employment situation, to explore the possibilities for* creation of (employment opportunities, and Prof. P. C. Maha-lanobis, fully supported by Jawahar-lal Nehru, took the lead in this matter. The Third Five Year Plan also carried forward that to some extent. From the Fourth Five Year Plan onwards even that assessment of the employment situation and unemployment if you like to call it, more or less has been given up. It has been virtually given up although a few paragraphs de appear there.

Now, Sir, the experience of planning has made a few things clear. I should like to know from the Government whether they are drawing the correct lessons from it. Is it not a question of allocation of funds or investment only. The Second Five Year Plan thought that employment potential or creation of employment opportunities could be related to the investments. And when they made certain allocations for investment under various heads, industry, agriculture and so on, they came to the conclusion that having made this investment, they would expect that employment opportunities would grow by such and such percentage. The figures showed thsit the expectations were not at all fulfilled. On the contrary, the backlog of unemployment grew, and the creation of new employment opportunities lagged behind the new entrants to the labour market. The result is that the volume • of unemployment went on increasing I year after year, Plan after Plan and now we are where we find ourselves today. There cannot be any change. Here, Sir, the role of the private sector has been the most deplorable. I have got one figure which I got just now. During 1971—76, the private sector, in the organised sector, created only about 66000 jobs. As against that, the public sector much maligned by the monopolist, is estimated to have created 1.9 lakh jobs, nearly two lakh jobs. This is the record. Even it is not satisfactory for the public sector. But always you will find that the private sector which had been given so much of concession, industrial licences and other facilities on the ground that they will help create employment opportunities had broken those commitments, and there the rate of creation of new employment opportunities had declined.

There has been a great betrayal by the monopolist sector because they believe not in the labour intensive but in the capital-intensive and other methods also, There has not been any creation of employment opportunities. Now, Sir, We have got this situation. Here, for example, in the Hazaribagh coalmines, the lands of the tribals were acquired. But the tribals did not get the jobs. You can understand the discontent, and the firing took place on 3rd February, Some thing is happening in Visakhapatnam. Now we find in some other places that notices are served. During the strike in Bangalore, notices were served by some people to the outsiders to go out of Bangalore. Well, such things are also happening. Therefore, Sir, the

situation is extremely serious I say. What is needed is structural changes in our economy. Here, Sir, the agricultural sector is very important from the point of view of creation of employment opportunities. Sir, some years back agricultural labour accounted for 50 million of the population, five crores. Today it is 67 million. But, as you know very well, even Mr. Sanjiva Reddi said the other [1] day, in his district the minimum* wage formula is not being implemented. They do not get even Rs. 2J a day. Such is the position. Here you have a vast segment of human population in our country which is left to the tender mercies of landlords, exploitation without any promise of employment opportunities and are left to their fate. At best, they get some seasonal employment. For the most part of the year they are not employed. Many economists have calculated that for a majority of weeks in a year our workers in the rural areas do not have work. This is unemployment in man hours or whatever you may call it. This is one source of unemployment. Land-lessness is growing and from land-lessness they become agricultural labourers and then, Sir, there is this kind of capitalist invasion in agriculture, tractors and other things are coming.

We find the rural population is being pauperised and they are without any employment. There is no restructuring of the agricultural economy or reorganisation of the agricultural economy which is why the poor peasantry and the agricultural labourers are subjected to such condition of perpetual and growing unemployment. Well, not wonder that poverty stalk$_s$ the land and an overwhelming majority of the poor agricultural workers and poor peasants live below the poverty line. In fact, in conditions of utter destitution most of them live. Sir, this is another problem.

In the industrial areas also and in the urban areas you find unemployment is growing and one thing is causing us great anxiety with very grave social implications. Well, Sir, it is the educated unemployed persons. It is not merely the graduate, engineers, and so on. People are educated, young people, and they are unemployed and when they are unemployed, well, you can understand what happens. You have seen what had happened in other countries in such situations. They become subject to all kinds of demagogy and propaganda apart from the suffering, human suffering, it involves. Not only it depresses the living standard of the family but it also cause$_s$ so many other hardships. If in your family two persons are unemployed, then your standard of living as a family unit is going down, event if y°u ^{ar}e gainfully employed, and your emoluments are goin" up. This is the situation And, we find we are in the midst of this situation

Now, many of these problems that we see among th$_e$ middle classes, educated middle classes, among the student middle classes, are taking place against the background of growing unemployment and ther$_e$ is no promise of future employment for those who are coming out of universities and colleges. Our children, daughters and sons, are coming out without any prospect and they cannot be put up with the promissory note on the future, on the heavens, as some poet said. They want Job$_s$ here and now, doctors, engineers, technicians and others who have passed. But what happens is that they go and line *up.* beifore employment exchanges for som$_e$ jobs. For th$_e$ job of a peon thousands of graduates apply. TTiis is the situation in which we are. Well, we are in the midst of, or are supposed to be on the threshold of the Sixth Five Year Plan. Well, what is the use of talking to us about Plans that we had?

Many years back I asked the Planning Minister how many Plan.? it would take the country to have the whole country unemployed?

[Shrj Bhupesh Gupta]

The rate at which every plan was producing unemployed persons a question came to our mind as to how many plans it would require to have the adult population of the country unemployed. "Now, you may take it as a sort of joke but it is a sad commentary on our affairs. How Ts it that we are proceeding from plan to plan; we are investing huge amounts, resorting to deficit financing and other things, and yet unemployment problem is nowhere near solution? It is getting aggravated, causing great threat, in fact bringing the society to the point of exploitation. I am not saying that in our country the same thing would happen. But what happened in the post world war I? What happened in Germany, you know it. Unemployment had been exploited there by the fascists. Unemployment had been exploited everywhere by demagogues and reactionaries in order to build up by sheer deceit and demagogy, their popular way to strike down the very fabric of democracy, and establish a fascist rule. I am not saying that we are envisaging this thing. But are not the reactionaries in our country to exploit this unemployment problem? They are bringing in The caste issues; they are bringing in oTher issues; they go against the reservations to which we are all cbmmitttd here. Now, when we cannot solve the problem, all these jthings come in, and all these are a fall-out of a bigger problem. And there are agencies, social and political forces in the country who want to exploit these things and who, in fact, exploit them in order to push up their designs. This is what I would like to say.

As far as what she has said is concerned, what can I say? We have seen all the plans. Very fine sentiments had been spelt out. I have seen here from those Benches, Pandit Jawahar-lal "Nehru, with passion and eloquence, in his characteristic fine language, drawing up a picture of country which would be flowing with milk and honey, with every young man getting a job by the time of the Fifth Five-Year Plan. But Jawahailal Nehru's words could not be realised, not because Pandit Jawaharlal Nehru did not personally mean it, but the system itself rules it out, not matter whether it is Gandhiji or Pandit Jawaharlal Nehru. It is this system itself, this capitalist system, in which exploitation is so entrenched, about which Mr. Venkataraman is very proud in the name of mixed economy. So long as this system remains; in this manner, with all its soullessness, with all its ruthlessness, with all its defiance of society, with all its vulgarity and brutality and inhuman approach, problem of unemployment cannot be solved. That you must realise. And [l0r] that, you need disbnnfTTng of monopoly capital, re-structuring of the economy, development of the public sectors on a much vaster scales, carrying out radical agrarian reforms, elimination of the dismal situation of the countryside especially, uplifting the poorer sections of the peasantry, and for that, you must introduce' radical land reforms. Even the land ceiling laws are not implemented. Sir, only 24 lakh acres of land have been,distributed so far under the revised ceiling laws. This is the claim of the Government. When the Planning Commission itself says that there must be at least 50 million acres available as surplus. Surplus lard should be available for distribution This is the position as far as the estimate is concerned, and this is the performance. Even what you have identified, you have not been able to distribute because vested interests in the rural areas are coming in the way. And these are the very people who are also responsible for creation and aggravation of the unemployment.

One word more. Sir, this is not accidental. Under capitalism, monopolists and exploiters want an army of unemployed. This gives them a better bargaining position. If the unemployed are there, -;Tiey are in a position to deal with the people who are

on jobs, deny them their demands, throw them out of their jobs, carry out retrenchment, declare lock-outs and so on and get new recruits from the army of unemployed. This is what is happenig in our country also. That is why, the system i$_s$ not only anti-employment, the system wants the unemployment problem to be aggravated for the same class interests for which they grab concessions from the Government, indulge in profiteering and raise prices of essential and other commodities, indulge in black-marketing and so on. Therefore, I demand. I do not know whether I should demand. I think, it stands to reason that any sensible solution, any serious and sensible solution, to the problem of unemployment, would definitely require a rethinking on the basic policies and restructuring and reorganising of our national economy in a manner which will bring about balance in the matter of production and employment. Production should *Toe* employment-oriented. Mer$_e$ increase in production does not mean that employment grows'. Then, in the rural areas, where agricultural production has gone up, employment opportunities would have increased-In th$_e$ same way, in the urban areas, where industrial production has gone up, unemployment would have been less. This is not so. We need change in our policies.

SHRIMATI RAM DULARI SINHA: Sir, first of all, I would like to say that our system, a$_s$ stated by the learned and experienced and oldest Member, Mr. Bhupesh Gupta, is not capitalistic. I would like to tell him that our system is democratic and we are proceeding towards socialism. The Sixth Plan outlay is the highest. The sectoral distribution is such that more money will be spent on agriculture, village and small industries, which are more employment-oriented. Various facilities are proposed to be provided for self-employment.

Sir, in regard to the tribal areas of Bihar, instructions have been given "to give the locals employment TrMn-dustries and mines. As I have already mentioned, th$_e$ policy envisaged by the Government is both for the urban and rural areas.

In regard to minimum wages, Government is looking into the matter and we have many times instructed the States in this regard. The latest reports show that minimum wages have been revised in almost all the States, for the agricultural sector.

SHRI BHUPESH GUPTA: You had not said anything about the Kerala scheme.

SHRIMATI RAM DULARI SINHA: Sir, Mr. Bhupesh Gupta has mentioned about the Kerala scheme and he has asked whether this can be applied by the Central Government. Sir, it is not only Kerala which" is giving unemployment benefit or unemployment relief to the unemployed; there are also other States which are doing this. Out of th$_e$ 22 States and Union Territories, eight States have got their own unemployment allowance or unemployment benefit schemes. It is for the Stat$_e$ Governments to introduce or not to introduce such kind of schemes. We are not in favour of Unemployment doles.

SHRI PATTIAM RAJAN (Kerala): Which are the States?

SHRIMATI RAM DULARI SINHA: The State$_s$ are: Punjab, Kerala, West Bengal, Gujarat, Maharashtra, Kar-nataka, Rajasthan and Tamil Nadu. We have also heard from Bihar and Andhra Pradesh that they are proposing to introduce some kind of Un-employmenf allowance schemes.

SHRIMATI HAMIDA HABIB-ULLAH: What about U.P.?

SHRIMATr BAM DULARI SINHA: We have not heard anything from U.P.

श्री प्यारेलाल खन्डेलवाल (मध्य प्रदेश): उपसभापति जी, बेरोजगारी की समस्या एक बहुत अहम और राष्ट्रीय समस्या है और

[श्री प्यारेलाल खांडेलवाल]

इस समस्या पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए । आजादी के बाद जितनी योजनायें बनी उन योजनाओं में हर योजना के बाद देश में बेकारी बढ़ती जा रही है और आज हालत यह है कि बेकारी से परेशान हो कर हिन्दुस्तान के नौजवान सड़कों पर आ रहे हैं और आज देश में जो अशान्ति और किसी-किसी प्रान्तों में जो कानून और व्यवस्था की खराब हालत देख रहे हैं उसका सबसे प्रमुख कारण यह बेरोजगारी की समस्या ही है । लोगों को हर बार यह आश्वासन दिया गया कि एक पंचवर्षीय योजना खत्म होने के बाद लोगों को काम मिलेगा लेकिन कुछ हुआ नहीं । फिर दूसरी योजना के बाद आश्वासन दिया गया फिर तीसरी के बाद आश्वासन दिया गया लेकिन स्थिति यह है कि आज जो आंकड़े अभी सदन के सामने रखे गये वे ही इस बात का सबूत हैं कि देश में इतनी पंचवर्षीय योजनायें बनने के बाद भी बेकारी की समस्या बढ़ती रही । हालत यह है कि आज सरकार के पास आंकड़े ही नहीं हैं कि हिन्दुस्तान में कुल कितने लोग पढ़े लिखे बेरोजगार हैं और कितने बेपढ़े लोग बेरोजगार हैं । न ग्रामीण क्षेत्रों की संख्या उन के पास है और न शहरी क्षेत्रों की संख्या उन के पास है । हालत यह है कि चार पंचवर्षीय योजनाओं के बाद तो सरकार ने आकड़े रखना ही बंद कर दिया कि कितने बेरोजगार हैं । लेकिन जो आंकड़े प्राप्त हैं, अभी पिछली 3 जुलाई 1980 को श्रम मंत्री जी ने जो आंकड़े दिये हैं उन को यदि मान लिया जाय तो उस के हिसाब से एक करोड़ 48 लाख इस देश में बेकार हैं और मैं मानता हूं कि यह आंकड़े पूरी तरह से सही नहीं हैं । अगर ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति को देखा जाय तो मेरा अनुमान है कि आज भी गांवों में दो करोड़ से अधिक लोग या तो बेकार हैं या अर्ध-बेकार हैं । उन के पास कोई काम नहीं है । साल में कुछ महीने वे काम करते हैं और बाकी समय में बेरोजगार रहते हैं और ऐसी स्थिति में जब बेरोजगारी की समस्या इतनी विस्फोटक है तो देश में उन लोगों को अवसर मिलता है कि जो देश की शान्ति और व्यवस्था को भंग करना चाहते हैं। या ऐसी ताकतों को अवसर मिलता है कि जो विदेशी हैं और देश में घुसने की कोशिश करती हैं । तो ऐसी स्थिति में मैं चाहता हूं कि सरकार इस संबंध में कोई समुचित नीति अपनाये । हालत यह है कि ग्रेजुएट्स और हायर सेकेंडरी भी बेकार हैं । 35 लाख तो ऐसे हैं कि जो पढ़े लिखे हैं और बेरोजगार हैं । जो पोस्ट ग्रेजुएट्स और ग्रेजुएट्स हैं और हमारे देश में कहा जाता है कि टेक्निकल लोगों की कमी है । लेकिन जो आंकड़े सरकार ने अभी तक बताये हैं उस के हिसाब से इस देश में 19,500 इंजीनियर बेकार हैं और 13,700 डाक्टर्स बेकार हैं और इनमें 1500 डाक्टर्स ऐसे हैं कि जो एमएस और एम डी हैं । ऐसे पोस्ट ग्रेजुएटस मेडिकल कालेज के लड़के भी आज बेकार हैं और उन को सरकार काम नहीं दे पा रही है । श्रीमन् मेरा यह निवेदन है कि सरकार को इस संबंध में अपनी नीति में परिवर्तन करना होगा और जब तक सरकार की नीति रोजगार मूलक नहीं बनेगी और जब तक वह श्रम प्रधान नहीं होगी आदमी को काम देने की नीति नहीं बनेगी तब तक देश की बेकारी की समस्या हल नहीं हो सकती है । और इस लिये जो विकास की योजनायें हैं उन में दस प्रतिशत की दर से विकास की योजनायें, जब तक नहीं बनेंगी तब तक जिस तेजी से इस देश की जन संख्या बढ़ रही है और जिस तरह से यहां की बेकारी बढ़ रही है, सरकार इस बेरोजगारी की समस्या को हल नहीं कर सकती । मैं इस संबंध में अपने कुछ सुझाव माननीय मंत्री जी के सामने रखना चाहूंगा और मैं चाहता हूं कि इस संबंध में सरकार कुछ निश्चित नीति अपनाये और यहां पर हम को कुछ आश्वासन दे ।

पहली बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि सरकार भारत संविधान में परिवर्तन करे और वर्क टु राइट काम को मौलिक अधिकार में जोड़ने के लिये प्रस्ताव लाये। मैं यह कहना चाहता हूं कि हर बार वायदा मिलता है लेकिन गरीब लोगों को काम नहीं मिलता। अगर सरकार ने संविधान में कोई संशोधन किया और काम के अधिकार को मौलिक अधिकारों में जोड़ लिया तो उस के लिये सरकार की जवाबदारी होगी और लोगों को काम मिलेगा। इस लिये मैं चाहता हूं कि इस बारे में सरकार कोई निश्चित घोषणा करे।

सरकार दूसरी व्यवस्था यह बनाये कि बेरोजगार वर्ग के पढ़े लिखे लोगों को, अनपढ़ों को सरकार बेरोजगारी भत्ता दें। तीसरी बात, शिक्षा नीति में ऐसा परिवर्तन किया जाना चाहिए जिसके कारण शिक्षा समाप्ति के पश्चात् आदमी को काम मिल सके, बेकारों को काम मिल सके, शिक्षा नीति में ऐसा मौलिक परिवर्तन होना चाहिए। सभी लोग यह महसूस करते हैं कि शिक्षा नीति में परिवर्तन हो, लेकिन आज तक इस सम्बन्ध में कोई निश्चित रूप से नीति निर्धारित नहीं हुई। हम चाहते हैं कि इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षाविदों की और ऐसे कुछ लोगों की एक परिषद बनाकर राउंड टेबुल कांफ्रेंस में बैठकर कोई नीति निश्चित की जाए और वहां पर बहस करके एक राष्ट्रीय नीति निर्धारित की जानी चाहिए। शिक्षा के सम्बन्ध में रोजगार मूलक नीति हो यह मेरी तीसरी मांग है।

चौथी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि आखिर हिन्दुस्तान की अधिकांश जनता गांवों में रहती है और जब तक ग्रामीण क्षेत्र में छोटे उद्योग, लघु उद्योग और ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्साहन सरकार नहीं देगी तब तक बेकारी की समस्या हम जो चाहते हैं उतने पैमाने पर हल नहीं हो पाएगी। तो क्या सरकार अपनी नीति में ऐसा परिवर्तन करेगी कि जिस से छोटे उद्योग ग्रामीण उद्योग गांवों के कारीगरों, छोटे-छोटे आदमियों को प्रोत्साहित किया जा सके। इस प्रकार के उद्योग धंधों में सरकार उनको मदद करेगी ?

एक बात मैं और कहना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि सब से महत्वपूर्ण बात यह यह है कि छह महीने के अन्दर सरकार ने एक ऐसा आयोग का गठन करने की घोषणा करनी चाहिए जो राष्ट्रीय युवा आयोग के रूप में सरकार की इन सारी नीतियों पर विचार करे और कोई नीति निर्धारित करे। क्या इस प्रकार से सरकार एक राष्ट्रीय युवा आयोग का गठन करने का विचार रखती है।

एक बात जो मैं आखीर में कहना चाहता हूं कि वह यह है कि सरकार ने विशेष धारक बांड की जो योजना चलाई है, सरकार की अपेक्षा है कि उससे बहुत सा काला धन बाहर निकलेगा। अगर सचमुच सरकार की इच्छा है तो सरकार इस बात की घोषणा करेगी कि धारक बांडों से जो पैसा आयेगा इन सारे बांडों का पैसा उन वास्तविक बेरोजगारों को दिया जाएगा जिनके पास आज कोई काम नहीं है ? उनको सरकार सस्ते ब्याज के ऊपर कम ब्याज के ऊपर पैसा बेरोजगारों को देगी ताकि वे छोटे-छोटे उद्योग लगाकर काम धंधे में लग सकें। यह एक नई बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और चाहता हूं कि सरकार इस पर विचार करे।

श्रीमन्, परिवार नियोजन और बेकारी इन दोनों का आपस में सम्बन्ध जुड़ा हुआ

[श्री प्यारेलाल खण्डेलवाल]

है। मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार क्या यह विचार कर रही है कि जिन लोगों ने परिवार नियोजन कराया है या करायेंगे आप उन्हीं को सरकारी ऋण देंगे, बैंकों से ऋण दिलावायेंगे किसी उद्योग के लिए ? इस बारे में सरकार कोई विचार करने जा रही है ? श्रीमन्, मैंने सारे प्रश्न आपके सामने रखें हैं, मैं चाहता हूं कि कोई निश्चित नीति हो तो तो मंत्री जी इन पर जवाब दें ।

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : श्रीमन् माननीय सदस्य ने बतलाया कि जितनी भी हमारी योजनायें हों वह जाब-ओरियेंटेड होनी चाहिए । मैं उन्हें बतलाना चाहती हूं कि हमारी जितनी भी योजनायें हैं जिनका मैंने जिक्र किया है, वह तमाम जाब-ओरियेंटेड हैं। हमारी प्रधान मंत्री इंदिरा जी स्वयं आर्थिक और सामाजिक परिवर्तनों की प्रतीक बन चुकी हैं। जहां तक संविधान में संशोधन की बात माननीय सदस्य ने कही है उसके सम्बन्ध में मैं उन्हें याद दिलाना चाहती हूं कि हमारे संविधान के डाइरेक्ट प्रिंसिपुल्स में ही देश के तमाम नागरिकों को ईक्वल राइस एण्ड ईक्वल आपर्चुनिटिज अबव कास्ट, क्रीड, रिलीजन एंड सेक्स लिखा हुआ है और इसी को मद्देनजर रखते हुए हमारी नीतियां और कार्यक्रम बनते हैं और कार्यरत हैं ।

श्री प्यारेलाल खंडेलवाल : श्रीमन्, मैंने एक राष्ट्रीय युवा आयोग की मांग की है और विशेष धारक वांडों के बारे में पूछा है आपने उसका जवाब नहीं दिया ।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : वह मैंने सुन लिया हैं ।

used to be sung by a blind singer in th$_e$ local trains! in my region. He used to sing, even during the darkest days or the most dreaded days of the Emergency; In tVii$_s$ unfortunate country of ours tt is a sin to be born, but it is forgotten that a man is bom not just with a stomach but also with two hands. Unemployment is a tragedy not only for the individual who is unemployed, but it is a national tragedy as well.

Human resources are, in a way. th$_e$ greatest asset that a country may possess, but it is unfortunate that in our country in spite of all the talk of planning and even though w.e are on the threshold of the Sixth" "Plan, the one thing wfiicTi is utterly lacking is human refource planning. It would b$_e$ clear from tte divergent figures that are being provided by the spokesmen of the Government at different stages regarding unemployment. Today itself, if I am not wrong, the Minister quoted a figure, at the very outset, that th$_e$ number of uneducated-unemployed in our country is 120 lakhs and that the number of educated-unemployed is 34.72 lakhs. Ready figures are available, which are completely at variance with these figures, and I am tempted to say that this figure, as supplied by the "Minister, may be characterized as the understatement of the century regarding unemployment in this country. Only the other day, during the Governors' Conference, the President of 'fire country observed— as reported in the press—that in this country 50 per cent of the people live below the poverty line. What is the position of '.his SO per cent of people who live below the poverty line? Have they got any employment? Now, if the Government does not have proper appreciation of this problem, if they just go on reiterating, by rote, certain figures$_i$ incomplete, in adequate figures designed only to cover the real malady, then it won't be possible to solve this problem which is facing us—if this dangerous and explosive situation is

PROF. SOURENDRA BHATTACHARJEE: Mr. Deputy Chairman, Sir, I am reminded of a song which

not appreciated by the ruling party. It is no use blaming the interregnum of the three years of the Janata Party.

Since the First Plan the problem of unemployment has been on the increase. The Minister tried to explain it away by saying that the stress on basic and heavy industry was responsible for this and that this emphasis was during the Second Plan only. But when we are on the threshold 'of the Sixth Plan which, we were told, was finalised with great promptitude by the present Government, what is the position? There has been no abatement in the spiralling growth of unemployment. What is the extent of it? That must be fully realised and appreciated by the Government if any dent has to be made on this problem. It must be understood, when more than six million educated unemployed are there, when the number of uneducated-unemployed runs into hundreds of millions, that it is necessary to attack this problem with a determination with a conviction and not just *to* wish away the problem by quoting certain figures. A statement from a Member of the Planning Commission, Mr. Swaminathan said that *by* the end of the Five-Year period it may be possible to create 7 million jobs, whereas the job requirement would be 35 million, according to his estimate.

SHRI KALYAN ROY (Wes Bengal) : What about the people who have been thrown out of employment on account of the closures? .

PROF. SOURENDRA BHATTA-CHARJ.EE: That is, 20 per cent of the problem may be touched this way or that way. The Minister quoted the plan. This is the estimate by an hon. Member of the Planning Commission. So I would like to know whether the depth of the unemployment problem has been fully appreciated by the Government. In addition, there is the problem, as has been referred to by the hon. Member, Shri Kalyan Roy(of these who are being thrown out of employment.. So my question to the Minister would be this Just now she referred to the unemployment...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You put the question.

PROF. SOURENDRA BHATTA-CHARJEE: .. .allowance provided in certain States. The question was originally raised by Shri Kalp Nath Rai, but in reply only pleasantries were exchanged. My specific question is: Would the Union Government formulate a scheme of unemployment insurance all over the country? All these schemes have been formulated under the Non-Plan head. What I want to know is whether under the Plan head a uniform type of scheme would be evolved for the whole of the country. Right to work should be a Fundamental Right, though it was opposed by Ruling Party, Janata Party and Congress (U) together. Now, would the Government be prepared to undertake this responsibility of evolving an unemployment insurance scheme all over the country, not in driblets?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now you conclude.

PROF. SOURENDRA BHATTA-CHARJEE; I am coming to the question.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: There are so many questions. It has been a two-hour-discussion.

PROF. SOURENDRA BHATTA-CHARJEE: I will take less time if there is no interruption.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You have already taken eight minutes.

PROF. SOURENDRA BHATTA-CHARJEE: Yes I have taken; but I don't take time very frequently.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You are only repeating.

PROF. SOURENDRA BHATTACHARJEE: NO, I am not repeating. The second question is: Will the Government lay stress on labour-intensive. ..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: This has been covered.

PROF. SOURENDRA BHATTACHARJEE; This has been covered, but not replied to. In spite of automatization everywhere, would they make a deliberate attempt aimed at maximising employment and stopping indiscriminate automatization. The third question is: What programme does the Government propose to undertake in order to employ the surplus population m the agricultural field?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The statement is there. Don't repeat all these things. You say something new that is not there.

PROF. SOURENDRA BHATTACHARJEE; And how the total public employment potential will be created and how the unemployed manpower will be utilized, should be clearly stated by the Government.

SHRIMATI RAM DULARI SINHA: Sir, we are proceeding towards implementation of the schemes with determination and zeal, as suggested by the hon. Member.

योजनाओं के सम्बन्ध में और हमारी नीति के संबंध में उन्होंने कहा है । लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारी योजना और हमारी नीति पर कोई अंगली नहीं उठा सकता है । हमारी नीति, हमारी योजना क्या है, यह सर्वविदित है । हमारी नीति पीस एंड प्रोग्रेस की है । हमारी योजनाएं सर्वांगीण विकास की है । गरीबी और बेकारी की समस्या के समाधान की है । माननीय सदस्य ने सजेस्ट किया है कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट को अनइम्प्लाइड लोगों के लिए कोई स्कीम बनानी चाहिए । उसके संबंध में मैं कह चूकी हूं कि कुछ स्टेट्स गवर्नमेंट्स है जिन्होंने इसको लागू किया है । जहां तक हमारा सवाल है,

It has been discussed many a time in this rvery House and in the other House also, but it does not seem to be feasible. We prefer to generate employment by productive utilization o* the resources available, as I have already said.

लेकिन मैं एक बात आपके सामने कहना चाहती हूं कि जब उन्होंने संगीत की बात कही तो मुझे लगा कि वे सचमुच कुछ श्रुतिमधुर संगीत सुनायेंगे पर निराशा हाथ लगी । एक जमाना था गुलामी का भारतवर्ष के अन्दर, जब हम खुद कहते थे कि "छप्पर से धुआं निकला बहुत दिनों के बाद, कौवों ने दो बोल चली बहुत दिनों के बाद । माननीय सदस्य को शायद मालूम नहीं होगा कि मैं खुद अपने विद्यार्थी जीवन के दिनों से ही ट्रेड

3 P.M. यूनियन वर्कर रही हूं । और हर फील्ड में, क्षेत्र में चाहे इंडस्ट्री का क्षेत्र हो माईन्स का क्षेत्र हो या एग्रीकल्चर सेक्टर हो, सबमें काम किया है और एक जमाना था जब बहुतों को एक टाईम का भोजन मयस्सर नहीं होता था । एक खेत काटती हुई बालिका एक गाना गा रही थी और मैं स्वयं सड़क से गुजर रही थी तो मैंने दो पंक्तियां बनाई थीं उसकी दर्दभरी भूख से पीडित गीत को सुनकर :

"अहा देख तो लो बाला को, यहां समीप
अकेली है,

काट रही कुछ गाती है, आती जाती
अलबेली है,

काट काट फिर बांध बांध, निज व्यथा
हृदय की उकसाती,
सुनो सुनो जग प्राणी जिससे आज तराई
भर जाती है ।
हंसिया साथ हृदय जलता था, इसको
मैंने लख पाया,
गिरि शृंग तक जाने पर भी, कानों में
था गूंज रहा,
किन्तु दूर हो गया पलों में, लगी देखने
यहां वहां ।।"

लेकिन जमाना बदल चुका है । आजादी के बाद गांधी जी के नेतृत्व की रोशनी में, जवाहर लाल नेहरू जी के पथ प्रदर्शन में, शास्त्री जी और मौलाना आजाद और इंदिरा जी के नेतृत्व में आज हम सिक्स्थ फाईव इयर प्लान के दौरान में घुस रहे हैं और न जाने कितनी आर्थिक और सामाजिक तरक्की की नीतियां बना चुके हैं, कितने कार्यक्रम बना चुके हैं और बेरोजगारों को हर तरह से राहत देने की दिशा में सरकार ने सफलता पायी है और पाने जा रही है । माननीय सदस्य को यह मालूम होना चाहिए, उन्हें यह अहसास होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए और उन्हें हमारे कार्यक्रमों के इम्प्लीमेंटेशन में सहयोग देना चाहिए ।

श्री उपसभापति : श्री शहाबुद्दीन । अब आप देखिये इस कविता से कुछ... (व्यवधान)

श्री सैयद शहाबुद्दीन : हम तो कवि सम्मेलन में पहुंच गये हैं ।

SHRT BHUPESH GUPTA: Now we have a duet between the two.

SHRI SYED SHAHABUDDIN; Mr. Deputy Chairman, Sir, we are dealing with a very serious problem, in my view the most serious problem in India. Unemployment is the basic malaise of the Indian economy. It is a universal virus which is very non-discriminatory in its behaviour. It attacks the rural environment and the urban milieu alike. It affects all classes, castes and groups irrespective of their origin or their place of residence. It attacks the educated and the illiterate uniformly.

Mr. Deputy Chairman, from the discussion we had it is clear that unemployment in independent India is like a hydra-headed monster; the more we try to kill it, the more heads it grows.

SHRI J. K. JAIN (Madhya Pradesh): it is like Ravana.

SHRI SYED SHAHABUDDIN; It is indeed the Ravana of the Indian economy. What we need is a Rama. The very fact that 50 per cent of the people live below the poverty line today is an indication, if not of total unemployment, certainly of under-employment.

Unemployment has a dehumanising influence on the individual. It is also socially disruptive. I feel, Mr. Deputy Chairman that apart from causing economic distress, it causes all sorts of social tensions, it causes political agitations, it causes administrative corruption. It in fact dehumanises the society as a whole. What is the dignity of a man who cannot even offer bread to his children?

Mr. Deputy Chairman, we know that the population has been increasing, expanding, but is the economy expanding at the same rate? We know it is not. It is the absorbing capacity of the economy that we have got to increase. I find that the population is increasing by about 13 or 14 million per year. The number of new seekers entering the labour market, the new faces, per year comes to 6 to 7 million, and the economy simply cannot absorb them. Obviously, there

[Shri Syed Shahabuddin]

is something wrong with our planning. We have to examine the planning objectives that we had before us for the last 30 years? Mr. Deputy Chairman, in 1978 when the draft Five Year Plan for the period 1978—1983 was being drafted, the planners said, "Man is the centre of our concern". If that is so, then "employment should be the centre of our development activity." That is why in framing the draft they said, and I quote, Mr. Deputy Chairman;

> "The first objective being the objective within a period of 10 years the removal of unemployment and significant under-employment."

I am sorry, Mr. Deputy Chairman, that in the revised draft that was recently placed before the nation, unemployment has come down to the third level of priorities. Once again I quote: it says, as the third item: "Progressive reduction in the incidence of poverty and unemployment." The first two refer to growth, production and modernisation. What I am concerned with. Mr. Deputy Chairman is that this philosophy of development must change. We must again place Man who has creative capacity. The utilization of the productive force that he represents, the capital resource that he represents in the nation, at the centre of the scheme of things. It is not simply machine which would produce. It is not simply the productive capacity of our mills or the technology they use which would change the face of the country. I would, therefore like to put this question; How are we going to clear this backlog of unemployment which grows bigger with every successive Five Year Plan_ unless we are going to focus our basic attention on the removal of unemployment. Mr. Deputy Chairman, the Government must say very clearly that in its choice of technology the primary criterion shall be whether it is capital intensive or labour intensive, it has not yet been stated in unequivocal terms by the present Government at any stage. The Government must also see that when various projects compete for scarce resources, what will be the criteria for the determination of priority to a particular project, I would say, it should be its employment generation capacity. I would like the hon Minister to tell us whether the Government shares this view.

Mr. Deputy Chairman Sir, I know that production is essential and 1 also know that fragmentations of jobs or their redistribution amongst different sets of people is not going to ease the unemployment problem. We have to generate more jobs. So the manner of production mus:t be such that you reserve certain sectors of production for some sets of people or certain areas, so that employment benefits are stretched as far as possible.

I would like to know from the hon. Minister—and this is a very specific question—what was the increase in national employment, during the years 1977, 1978 and 1979. I would also like to know, if Madam Minister has got the figures. What is the increase in unemployment during the year 1980?

She has talked of self-employment. I would like to know; Has the Government set a target for the flow of institutional credit to encourage self-employment?

I would also like to ask this specific question. In i;he total development resources that are to be allocated under the' Sixth Five Year Plan what is the share of the rural sector and what share of the total resources is going to be spent in our villages and for developing our rural infra-structure.

Mr. Deputy Chairman, Sir, the Minister has talked about the Food For Work Programme. They have

given it a new name, i do not mind it. Let them continue the programme under any name. But I would like to know, what fault has been Committed by the programme of 'Anto-daya', what sin has been committed by the people at the lowest rung of the social ladder that they have decided to abolish the ^Antodaya' programme?

They talk about restricting monopoly. Every body knows that our industrial production is still under monopoly's strangle-hold th$_e$ national bourgeois is being strengthened more and more through contacts with foreign multi-nationals in the name of modernisation. 1 would like to know the methods adopted by the Government to mov$_e$ away from profit and consumption orientation and try to channel industrial production in the field,?! where it really benefits the largest number of people. I would like to know the target date from the hon. Minister when the employment guarantee schemes shall be available both in the urban and rural sectors throughout the country.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That will do

SHRI SYED SHAHABUDD1N: Unemployment allowance has been granted in some State$_s$ to the educated. I am not for doles. I would like the educated to be usefully employed, i would.like their knowledge and skill to be used for national development. I would like to ask whether they have any target date when all the educated unemployed shall receive this unemployment allowance, so long as they are unemployed.

Finally, I find from this statement that the hon. Minister has used various criteria. In some places she is very specific and she has quantified that a programme will generate the number of jobs. In other places, she is beautifully vague. She says "Generation of increasing employment opportunities in agriculture and allied sectors through massive irrigation programmes but gives no figures". There are some figures given in Item No. 2. In Item No. 3, there are absolutely no figures. In Item No. 4, there is a vague reference to 30 to 40 crore$_s$ man-days of employment per year. In Item No. 5, it says that so many persons will be benefited. I would ask the hon Minister to have uniform statistics and adopt uniform criteria for indicating the employment potential of various schemes. For the benefit of ignorant people like us, I would request her to define the term "standard person-years." I would then like to know what was "this figure at the beginning of the First, the Second, the Third, the Fourth, the Fifth and the Sixth Five-Year Plans.

SHRTMATI RAM DULARI SINHA: Eradication of unemployment is one of the main objectives in order to contain unemployment and poverty. Unemployment is our national problem and we have to tackle it. We have to cater to different objectives. But we cannot implement one programme and exclude others.

जहां तक माननीय सदस्य ने यह कहा कि हमारी नीतियों से, हमारे कार्यक्रमों से बूर्जुआ को मजबूती मिलती है, तो मैं बताना चाहती हूं कि हमारा लक्ष्य बूर्जुआ को मजबूत करना नहीं है, कैपिटलिस्ट्स को मजबूत करना नहीं है। हमारा लक्ष्य गरीबी को मिटाना है, बेरोजगारी को मिटाना है । जहां तक इम्प्लायमेंट का, अंडर-इम्प्लायमेंट का सवाल है, माननीय सदस्य ने कहा हमने अंडर-इम्प्लायमेंट को ध्यान में नहीं रखा है तो मैं उन को बतलाना चाहती हूं अध्यक्ष जी, कि सरकार जब नीति का निर्धारण करती है, योजनाएं बनाती है, तो उसका ध्यान पूर्ण रुप से बेरोजगारी और अर्ध-बेरोजगारी की तरफ रहता है; समाज के हर वर्ग का ख्याल सरकार रखती है

श्री सैयद शहाबुद्दीन : हुजूर, आखिर कम से कम एक सवाल का जवाब तो दे देतीं ।

DR. MALCOLM S. ADISESHIAH (Nominated); First of all I say that we have to define unemployment. The Government has defined a person as employed who get work lor 8 hours a day for 273 days. Anyone who does not fit into this definition is unemployed. So, my first question ig this. Am I right in saying that anyone who does not have work for 8 hours a day for 273 days is unemployed? In India unemployment arises not because of lack of complete employment. Nobody is involved in a situation like this. In western countries, either there is no work at all or full work. What happens in our country is this. There are two things. Either the wages are high and the working days are low as in Punjab and Haryana where the agricultural wages are high. But the number of days have declined because of mechanisation. The same is true of Kerala where the agricultural wages are very-high but the. working dajjs ar$_e$ low. Therefore, the annual wage for "the family is low. That is one reason for under-employment. The s^{ec}ond reason is that the wage earned is low though they are working for 360 days a year.. Therefore, Mr Deputy Chairman, am i right in saying that what we call unemployment is really under-employment in thi$_s$ country? Therefore, our poor unlike the poor in western countries are the working poor. All are working and poor. They are working at sub-minimal wages. That is my first question. My second question is this. I want to ask the hon. Minister whether she would agree with me that we really do not know the magnitude of the problem of unemployment so defined in this country. Sir, Mr. Bhupesh Gupta pointed out that the First Plan and the Second Plan have given some figures. But those figures are somewhat unreal figures. Now we are trying to refine the figures. But my second point is to tell the Government that in spite of 32nd round of NSS in spite of improved employment exchange statistics, we really do not know and in this country we have not perfected the system of collection of information of what is the order of our unemployment. Now, my third and th$_e$ last question is this. First I want to congratulate the Minister, as the others have done, on the: very good, very well formulated plans for employment in the Sixth Plan which the Minister has summarised in the statement that she has presented. Now, Mr. Deputy Chairman, Sir, as was said by Mr. Bhupesh Gupta or somebody, in every Plan w$_e$ are improving and improving the plan for employment. Plans are improving. Now, what is happening in the villages, what is happening in the block$_s$ to implement these plans we do not know. Therefore, my question to the Minister refers to what is now proposed under item 9 of the statement given— the District Manpower planning & Employment Generation Councils. I would like to ask whether these Councils instead of planning employment could also monitor$_i$ could collect data o^n what is really happening at the block level and the district level so that we will be abl$_e$ to answer the question a$_s$ to how many people have been actually employed this year and last year. All the Plans ar$_e$ very good. Now, the Plans are perfect. We cannot improve the plans. But could we get some monitoring on the implementation? These ar$_e$ my three questions, Sir.

SHRIMATI RAM DULARI SINHA: Sir, the Government is aware of the magnitude of both unemployment and under-employment. And, as. the hon. Member wa$_s$ saying, the Plans are improved to improve the lot of the poor and the downtrodden.

SHRI NARASINGHA PRASAD NANDA: Sir, what is th$_e$ answer?

Sir, if this kind of answer will come from the hon. Minister... *(Interruptions)*

SHRI P. RAMAMURTI (Tamil Nadu): Be chivalrous, Mr. Nanda. Sir, wonderful, beautiful poetry and poetic imagination is not reality. Of course, she has recited beautiful poetry.

SHRIMATI RAM DULARI SINK A: Based on reality.

SHRI P. RAMAMURTI: And I am saying that she is competing with Mr. Zail Singh.

SHRI BHUPESH GUPTA: They should be asked for a duet.

SHRI P. RAMAMURTI: I do not know if they are now out for a duet.

SHRIMATI RAM DULARI SINHA: But I cannot compete with you.

SHRI P. RAMAMURTI: I do not want a duet with you. You have a duet with Mr. Zail Singh.

Sir, they are talking on all these Plans and I am not concerned with it. I know what is going to be the result. We know the result of the previous Plans. I am not going to talk on the general question. I am asking myself a question, apart from the question of improving the Plans for bringing down unemployment, what is the practical reality? The practical reality is one where mechanisation is not necessary at all, mechanisation is being introduced. For example in the coir industry which is the mainstay of nearly 20 lakhs of people in Kerala, now mechanisation is being allowed by the Industry Ministry which means nearly 90 per cent of the 20 lakhs of people that are employed, they will become totally unemployed. Secondly, there is the ITI or whatever it is-That is the India Tobacco Company. There is a multi-national company which is engaged for example, in preparing the cigarettes. *(Interruptions).* Yes, it is the ITC, the India Tobacco Company. That was given the permission, the licence for mechanisation in curing the tobacco for the installation of some machine in Guntur. And as a result of that 75,000 women workers are going to be unemployed So, these are your wonderful policies but the practice is this. Sir, I am glad that the Minister of Commerce in the Textile Policy Statement has said that he is not going to allow expansion of loomage as far as textiles are concerned because h_e wants to improve the handloom industry. Reservation is all right. But the real question is that today the price of yarn is such that it is increasing day by day as a result of which the hand-loom weavers are not able to market their cloth and consequently the handloom weavers throughout the country are suffering in spite of all these things. Therefore, the existing employment itself is not being protected, the existing employment is being eroded, completely eroded. What to talk of creating employment? I will come to that later. Will the Government change its policy with regard to mechanisation of industries, especially of those industries where it is not necessary? When we talk of that you say, we must export, export and export more. Is it more export or more employment, which is more important? Therefore, will the Government give an assurance that they will reverse this policy of mechanisation in those sectors where it is absolutely unnecessary in the name of improving our export potential and creating more unemployment? These are the three questions that I have put concretely. I do not want to go into the whole question of basic policy.

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : उप-सभापति महोदय, औद्योगीकरण के दरम्यान विकास योजनायें और ग्रामीणीकरण दोनों चलता है और हम एक डैवलपिंग नेशन हैं और इस लिये हम दोनों को एक साथ ले कर चल रहे है और चलेंगे । माननीय सदस्य के सामने कुछ दूसरी तरह की कठिनाइयां है । हमारे यहां कई माननीय सदस्य आते हैं और उन से

[श्रीमती रामदुलारी सिन्हा]

बातें होती हैं और जो उनकी कठिनाई होती है उन को हम दूर करने का प्रयास करते हैं और करेंगे । लेकिन जहां तक एक्जिस्टिंग अनइम्प्लायमेंट का संबंध है उस के बारे में उन्होंने जो कुछ कहा तो सब कुछ 100 परसेंट सही नहीं होता है, लेकिन हम लोग बराबर कहते हैं कि सौ परसेंट सही है । हम इस दिशा में कार्यरत हैं । लेकिन डमोक्रसी में तो यदि 51 प्रतिशत होता है तो उसे ठीक माना जाता है और 49 हुआ तो उसे बेठीक माना जाता है । इस लिये मेरा कहना है कि हमारे प्लान का, योजनाओं का, कार्यक्रम का कोई ज्यादा दोष नहीं है, कुछ उस में आप लोग भी सहयोग दीजिए । कहीं आप लोगों से गड़बड़ी होती है और किसी किसी अन्य की वजह से गड़बड़ी होती है, लेकिन सब की जिम्मेदारी हमारी होती है । तो सरकार की स्थिति तो यह है कि :

"इन कफ्स के कैदियों को चहचहाना है मना ।"

श्री पी० राममूर्ति : सहयोग के लिये ही तो मैंने आप से सवाल पूछा था ।

REFERENCE TO THE COMMENDABLE WORK OF THE SCIENTISTS OF THE NATIONAL INSTITUTE OF OCEANOGRAPHY IN MINING OF POLYMETALLIC NODULES

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now we will take up special mentions. Yes, Dr. Najma Heptula. Please take only three minutes and not more than three minutes.

SHRI SfiRIDHAR WASUDEO DHABE (Maharashtra): Sir, I rise on a point of order.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Let her finish the special mention and then you can raise the point of order.

SHRI SHRIDHAR WASUDEO DHABE: Sir, 1. have got a point of order on the special mention itself. I want to raise a point of order. All right, it can be heard afterwards.

ME;. DEPUTY CHAIRMAN: Let her finish. Then I will hear your poin'; of order.

SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal): Sir, apart from the fact that she i$_s$ making a speical mention, she herself is a special mention.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, Dr. Najma Heptula.

SHRI BHUPESH GUPTA: You are making a special mention. You yourself are a special mention.

DR. (SHRIMATI) NAJMA HEPTULA (Maharashtra): Sir, I would like to make this special mention about the very important discovery by our own scientists who have been working in the National Institute of Oceanography. This is regarding the deep sea-bed mining and discovery of the polymetallic nodules which have been discoverd a few days ago as a New Year gift by these scientists'. Our Prime Minister has already congratulated them and I would like cur House to join us in congratulating our own scientists who are doing such kind of" research which is bringing honour to our country, because uptil now oily six nations, six dtejytejtopied countries, wei'e in this field, namely the Soviet Union, the United States of America, the U.K., France, W ist Germany and Japan. And now, India has entered the deep sea mining and we are the first country in the third-world countries.

Sir, apart from the fact that this is going to enrich our mineral resources, because the polymetallic nodules contain cobalt, nickle copper, manganese and traces of gold, it is said—it is estimated—that about 2,000 billion tonnes of these polymetallic nodules are present in our oceans' bed. This